PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Ecosystem damage, economic cause, buffer zone efforts — none of them have been replied. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are all so general. ...*(Interruptions)*... That is all general. ...*(Interruptions)*...

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Why is the Government ignoring these questions? Let the Minister reply. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; sit down. ...*(Interruptions)*... See, the Minister cannot reply to everything under the sun. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: He evaded your question. ...*(Interruptions)*... He has not replied to your question. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tapanji, I heard it. ...*(Interruptions)*... I heard it. So, I directed the Government. ...*(Interruptions)*... I told the Government to examine that question as to what can be done about it. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: He has evaded that question. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already given a direction to the Government to look into this issue of 'low-reported catch'. Even though the catch is high, the 'reported catch' is much low. I want the Government to examine it and I have said it already. *Mantriji,* the question is about the low-reported catch. Catch बहुत है, लेकिन 'reported catch' बहुत कम है। इसके बारे में थोड़ी inquiry करनी है, कुछ काम करने हैं। Okay. ...*(Interruptions)*... Now, let us take up the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017. Shri Prakash Javadekar.

GOVERNMENT BILLS - *Contd.*

The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

सर, 'सर्व शिक्षा अभियान' और 'राइट टू एजुकेशन' के कारण आज सभी जगह शिक्षा का विस्तार हुआ, लेकिन उस विस्तार में शिक्षकों को जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया

[Shri Prakash Javadekar]

है। पहली से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए D.El.Ed. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक चाहिए और अपर प्राइमरी में B.Ed. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक चाहिए, इस तरह के प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए थे, लेकिन वैसे शिक्षक नहीं आ पाए, इसलिए राज्य सरकारें अनट्रेंड टीचर्स लेती गईं। अनट्रेंड टीचर्स लेने की परमिशन भी दी गई और 2015 तक उन सभी अनट्रेंड टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए कहा गया था। वे qualification अर्जित करें, D.El.Ed या B.El.Ed., जो भी उन्हें करना है, उसे करने के लिए 2015 तक की मोहलत दी थी। आज की स्थिति यह है कि उनमें से 3 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग हो गयी, 1.5 लाख टीचर्स की एक साल की ट्रेनिंग हो गई और एक साल की ट्रेनिंग बची है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहले प्राइवेट स्कूल्स का उल्लेख ही नहीं था। जब हमने प्राइवेट स्कूल्स के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि आज इन स्कूल्स में 7 लाख अप्रशिक्षित, unqualified टीचर्स काम कर रहे हैं। इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के 7 लाख टीचर्स, 1.5 लाख ऐसे टीचर्स, जिनकी एक साल की ट्रेनिंग बाकी है और सरकारी स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख अनट्रेंड हैं, इन सबको मिलाकर आज 11 लाख टीचर्स D.El.Ed. या B.El.Ed. नहीं हैं। ऐसे में अवसर बंद करने से कैसे चलेगा? इतने लोगों को नौकरी से निकाल भी नहीं सकते, लेकिन छात्रों पर भी अन्याय नहीं कर सकते कि उनको अप्रशिक्षित शिक्षकों के हाथों से शिक्षा मिले, इसलिए उनको D.El.Ed. या B.El.Ed. करने के लिए दो साल की अवधि देने के लिए यह बिल लाया गया है। यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। अब यह सवाल है कि यह दो सालों में कैसे होगा? यह इसलिए होगा कि टेक्नोलॉजी ने एक नया अवसर पैदा किया है, जो हमने 'SWAYAM' प्लेटफार्म लाँच किया है, इस पर D.El.Ed. या B.El.Ed. के कोर्सेज़ इस अक्टूबर से ही प्रारंभ होंगे। यह 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी जयंती दिवस पर शुरू होगा। इसके लिए इन 11 लाख टीचर्स का रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच पूरा हो जाएगा। पहले ये रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद इन सभी को फ्री एजुकेशन मिलेगी। इनको कहीं भी कॉलेज ढूंढने के लिए नहीं जाना है। यह 'SWAYAM' क्या है? 'SWAYAM' में ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा है और ऑफलाइन ट्रेनिंग की भी सुविधा है। इसके तहत अच्छे प्राध्यापक लेक्चर्स देंगे, उसका material होगा, उसका tutorial होगा, उसका mid-discussion forum होगा, कुछ भी आंशका होगी, तो उसको वे पूछेंगे, उसका जवाब मिलेगा। उसके बाद परीक्षा होगी और सर्टिफिकेट मिलेगा।

जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा है, वे अपने कम्प्यूटर पर इसको कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है या ग्रामीण इलाके में, जहां ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, वे क्या करेंगे? ऐसे लोग टीवी के माध्यम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए टीवी पर जो कार्यक्रम दिखेगा, उसका नाम 'SWAYAM Prabha' है। 'SWAYAM Prabha' के तहत 32 एजुकेशनल चैनल्स हैं। दूरदर्शन के साथ हमारा टाइअप हो गया, एमओयू हो गया और आज 32 चैनल्स शुरू हो गए। यह लगभग हर भाषा में है, क्योंकि जो भी अप्रशिक्षित हैं, उनका जो प्रशिक्षण होगा, वह सभी भाषाओं में होगा। जो regional language में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको regional language में ही प्रशिक्षण देना पड़ेगा। यह कार्यक्रम टीवी पर दिखेगा, लेकिन इसके लिए फ्री डिश लगानी पड़ेगी, जो दूरदर्शन की होती है। इस डिश का सेट-अप बॉक्स इनको लेना पड़ेगा और इसमें 1,300 रुपए का खर्चा है। लेकिन अगर एक बार 1,300 रुपए खर्च किये तो उस पर जो कंटेंट आएगा, वह रोज दो-तीन बार दिखेगा। मान लीजिए कि कोई हिन्दी का अध्यापक है, यानी हिन्दी में पढ़ने वाला है या हिन्दी में परीक्षा देने

वाला है, तो D.El.Ed. और B.El.Ed. का हिन्दी चैनल अलग होगा और यह दिन में दो-तीन बार रोज आएगा। टीवी के माध्यम से वे अपने घर में अपनी सहूलियत के हिसाब से उस पाठ को देखेंगे, पढ़ेंगे। उनको materials, किताबें अलग से मिलेंगी। ये जो materials, किताबें मिलेंगी, उनके आधार पर वे स्वयं अध्ययन करेंगे, क्योंकि वे स्वयं पढ़ा ही रहे हैं, इसलिए उनको लेसन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका practical aspect चल ही रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए, यह theoritical अध्ययन अब online भी मिलेगा, offline T.V. पर भी मिलेगा और इससे दो साल में 11 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक पूरी तरह से शिक्षित हो जाएंगे, qualified हो जाएंगे। इससे देश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, टीचर्स का स्तर भी बढ़ेगा और आज, उनके मन में अब तक जो शंका थी कि कहीं हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, वह शंका भी दूर होगी। अब उनकी नौकरी तो नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें पढ़ना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से यह बिल सदन के सामने लाया गया है। मुझे लगता है कि सभी दलों की तरफ से इसे यहां समर्थन मिलेगा और जैसे लोक सभा में यह सर्व-सम्मति से पास हुआ, वैसे ही यहां भी पारित होगा। इतना ही कहते हुए, मैं इस बिल को चर्चा के लिए प्रस्तुत करता हूं।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K. Rahman Khan; not present. Shri Shamsher Singh Dullo.

श्री शमशेर सिंह दुलो (पंजाब): माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*]

यह बिल - Elementary Schools में Right of Children to Free and Compulsory Education देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि हिन्दुस्तान में सभी बच्चों को free education दी जा सके। Education के साथ ही उनका development हो सकता है, और जो बच्चे बेसहारा हैं, under-privileged हैं, पूरे देश में उन सभी बच्चों को अब compulsory education मिलेगी। उन्हें पढ़ाने के लिए कई राज्यों में जो teachers रखे गए थे, उनमें कई qualified नहीं थे। उन सबको special training देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है, मैं उससे सहमत हूं। यह प्रावधान सबके हित में है।

हिन्दुस्तान के कृषि-प्रधान देश होने के कारण, हमारे गांवों में ज्यादा आबादी निवास करती है, भारत में लगभग 80 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांवों के स्कूलों और शहरों के स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा में जो disparity है, वह बहुत ज्यादा है। इस बिल के माध्यम से unqualified teachers को trained करने के लिए प्रावधान किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि 2002 में Education को भारत के संविधान के Preamble में शामिल किया गया था। उसमें standard of education का जिक्र भी किया गया। उसके बाद 2015 में, उसमें एक amendment हुआ। इस amendment के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में जो disparity पूरे देश में है, उसे दूर करने की कोशिश हुई। मैं समझता हूं कि आज हमें quality education की आवश्यकता है। यह ठीक है कि इसके

[श्री शमशेर सिंह ढुलो]

implementation में काफी short-comings हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में achievements भी काफी हुए हैं, education को compulsory भी किया गया है। इसके साथ-साथ, implementation में quality education का जहां तक संबंध है, उसमें भी बहुत short-comings हैं। हमारे Constitution के जो founding fathers थे, उन्होंने equal opportunity की बात कही है। Constitution में भी Equality in Education का प्रावधान है। इसी कारण हमारे संविधान में 86वां संशोधन हुआ। उसमें Right of Children to Free and Compulsory Education की व्यवस्था की गई। इसी तरह, वर्ष 2009 में एक ऐक्ट पास हुआ है, जिसमें लेजिस्लेशन किया गया। उसमें ऐश्योर किया गया कि जो एनरॉलमेंट हों, वे पूरी होनी चाहिए, पर मैं समझता हूं कि सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में डिस्पैरिटी है, एक गैप है। जो गैर-सरकारी स्कूल्स हैं, वे बिजनेस सेंटर्स बने हुए हैं। हम लोग भी सरकारी स्कूलों को पढ़कर निकले हैं। मैं खुद एक प्राइमरी स्कूल में से पढ़कर आया हूं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल था। लेकिन अब उन स्कूलों का स्टैंडर्ड पहले जैसा नहीं है। आप कम्पलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम मापदंड एक होना चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। स्कूल्स खुलते गए हैं, पर वहाँ टीचर्स नहीं हैं। आप गाँव में जाकर देखिए, वहाँ एक टीचर होता है और 500 बच्चे होते हैं। वहाँ उनकी बिल्डिंग्स भी कम्प्लीट नहीं होती। उनमें कही दरवाजे नहीं हैं, कहीं खिड़कियाँ नहीं हैं या कहीं डेस्क और कुछ नहीं हैं। भारत गाँवों में बसता है। गाँधी जी ने भी यही कहा था - "मेरे देश के ज्यादा लोग गाँवों में बसते हैं, वहीं रहते हैं।" अब आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड देख लीजिए। जहाँ से हम लोग पढ़कर आए हैं, मेरे जैसे यहाँ बहुत से मेम्बर साहिबान प्राइमरी स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में से पढ़कर, विद्या लेकर आए हैं, लेकिन अब लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों पर से उठता जा रहा है। Even एक रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। इस तरह का वातावरण अभी पैदा हो गया है। अगर इस तरह से लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों पर नहीं होगा, वहाँ वे अपने बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते, तो यह एक कमी है। यह सोशल मीडिया की कमी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि उनमें विश्वास पैदा करना है। जैसा कि कहा गया, वहाँ unqualified teachers रखे जाते हैं। जब वहाँ unqualified teachers रखे जाएँगे, तो फिर इस देश की तरक्की कैसे होगी? जिसको हम future of nation कहते हैं, जिस अध्यापक को हम नेशन बिल्डर कहते हैं, जब वे नेशन बिल्डिंग का काम नहीं करेंगे, तो इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। डा. अब्दुल कलाम जैसे बड़े लोग, जिनको "मिसाइलमैन" कहा गया और जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, वे सरकारी स्कूलों में से पढ़कर आए थे। हमारे बहुत से साइंटिस्ट्स, जज और हाई पोस्ट्स पर रहने वाले लोग हैं, जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं, क्योंकि पहले टीचर्स का एक मिशन था। जो मिशनरी टीचर होता है, वह बच्चों को भी उसी तरह की विद्या देता है, पर अब क्या हो रहा है? वे बिजनेस सेंटर्स बन गए हैं। उनके लिए सरकारी फंड भी है, सर्व-शिक्षा अभियान है, मिड-डे मील भी दिया जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ हाजिरी लगती है। उसको मॉनिटर करने के लिए टीचर्स पर एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आज कॉम्पिटीशन का जमाना है। आपको पता है कि इन्होंने पिछली दफा कहा था कि ये पाँचवीं और आठवीं कक्षा में एग्जाम्स कराएँगे, यह अच्छी बात है। जब हम पढ़ते थे, तब हम फट्टी पर लिखते थे और सुलेख के भी नम्बर मिलते थे। उस समय ये सारी बातें कॉम्पिटीशन लाती थीं। मेरा यह सज़ेशन है कि अगर अच्छी लॉट

पैदा करनी है, तो कॉम्पिटीशन पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जमातों में भी होना चाहिए। लेकिन, यह पता है कि टीचर भी यह सोचकर नहीं पढ़ाता है कि पाँचवीं तक तो फेल ही नहीं करना है, लेकिन जब बच्चा छठी कक्षा में जाता है, तब उसको ABC भी नहीं आती, उसको गिनती नहीं आती। इसलिए एजुकेशन में टीचर का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसको नेशन बिल्डर कहते हैं, लेकिन अब यह बिज़नेस बनता जा रहा है। हम प्राइवेट स्कूलों को फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। हम उनको बिल्डिंग बनाने के लिए जगह भी देते हैं और उनकी मॉनिटरिंग और फंडिंग भी करते हैं, पर क्या किसी ने कभी चेक किया है कि जिन कंडीशंस पर उन स्कूलों को हम सुविधाएँ देते हैं, उनके अनुसार क्या वे इकनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला देते हैं, क्या वे शेड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों को अपने यहाँ दाखिला देते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं? कोई रिजल्ट नहीं है। जावडेकर साहब अच्छा बिल लाए हैं। हिन्दुस्तान में जो फिगर्स दी जाती हैं, कहते हैं कि यह तो सरकारी फिगर्स होती हैं। हम गांव से बिलाँग करते हैं। हमें पता है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनमें से काफी बच्चे तो खाना खाकर स्कूल से घर पर आ जाते हैं। गांवों में ड्रॉपआउट कितना है, कभी यह भी चैक करना चाहिए कि स्कूलों में कितने बच्चे ड्रॉपआउट हैं, उनका परसेंटेज़ कितना है। सारे हिन्दुस्तान के बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गवर्नमेंट सोचती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो खानाबदोश हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, जिनका न घर है, न बार है, आज यहां, कल वहां, परसों वहां, हिन्दुस्तान में ऐसी जगह बहुत सी फेमिलीज़ हैं, जिनको सदियों से न घर मिला, न रहने को जगह मिली, न स्कूल मिला। आप देखोगे, हम जब जी.टी. रोड़ पर जाते हैं वहां ढाबों पर बच्चे काम करते हुए मिलते हैं। वे बच्चे होटलों पर, ढाबों पर बर्तन साफ करते हैं। फैक्टरियों में चले जाओ तो वहां भी बच्चे काम करते हुए दिखाई देंगे। घरों में भी छोटे-छोटे बच्चे सर्वेंट बनाकर रखे हुए हैं। सरकार करना चाहती है, उसकी नीयत ठीक है, करने की जरूरत भी है। लेकिन इन लोगों के बारे में सोचो, जिन्होंने सदियों से स्कूल का मुंह नहीं देखा। जो आदिवासी लोग हैं, उनकी वहां पर क्या हालत है, उनके बच्चे भूखे-नंगे फिरते हैं। वहां उनके लिए स्कूल है, बिल्डिंग है, परन्तु वहां अध्यापक नहीं है। टीचर्स की मेन्टेलिटी यह है कि वे गांवों के स्कूलों में जाना नहीं चाहते।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब समाप्त करें।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सर, अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपकी पार्टी के और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सर, सोशल चेंज लाने के लिए, इक्वेलिटी लाने के लिए तथा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो यह कि अच्छे टीचर्स होने चाहिए और उनको अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। उनके रिक्रूटमेंट का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, उनको बैटर ट्रेनिंग देनी चाहिए, मॉनिटरिंग का सिस्टम भी होना चाहिए, ड्रॉपआउट के बारे में भी देखना चाहिए। इसमें स्टेट वाले 40 परसेंट देते हैं। जो चाइल्ड लेबर है, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे फैक्टरियों में काम करते हैं, उनको देखने का काम लेबर मिनिस्ट्री का है कि उनको वहां से निकालें। वहां बच्चे इसलिए काम करते हैं कि वे मां-बाप का सहारा बनते हैं। कोई मां-बाप यह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे स्कूल न जाएं। परन्तु उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए साधन नहीं हैं। सर, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इतनी गरीबी है, इतने लोग बिलो पॉवर्टी

[श्री शमशेर सिंह ढुलो]

लाइन में हैं कि गरीबी को दूर नहीं किया जा सका, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, यहां डिस्पैरिटी है। आप कहते हैं कि हम समाज को एक करना चाहते हैं। समाज एक कैसे हो जाएगा? आप एजुकेशन को नेशनलाइज करो। ये स्कूल जो बिजनेस सेंटर हैं, उनके मुताबिक ही प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल होने चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप कन्क्लूड करिए।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: तीसरी बात, स्कूलों में कास्ट सिस्टम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, कॉलेजेज में हो रहा है। इससे गरीब लोगों का मनोबल गिरता है। कोई जमाना था जब शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल से बाहर बिठाया जाता था। अब तो वे लोग अंदर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर करना चाहिए और जो एजुकेशन स्कीम है, इसको लागू करने की जरूरत है। जो nomadic tribes हैं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए, आपका बहुत ज्यादा टाइम हो गया है।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त करिए।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: ठीक है, जो डेटा है, यह गलत डेटा है। आप एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए अथवा एक पॉलिसी बनाइए। सरकारी स्कूलों पर से गरीबों का विश्वास उठ गया है, इस विश्वास को दोबारा से बनाइए। आप जो राइट टू एजुकेशन की या कम्पलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, यह तभी पूरी होगी, जब लोगों के मन में विश्वास हो और वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन तो कर ही रहा हूं, मगर मैं यह सोचता रहा कि यह बिल लाने की नौबत क्यों आयी। उसका एक इतिहास भी है और जिसकी पहले इस सदन में कई सदस्यों ने चर्चा भी की है, सब लोग जानते भी हैं। मगर दोहराना भी जरूरी होता है क्योंकि हमारे देश में विचारधाराओं का और विशेष रूप से विचार-सूत्रों का एक दौर चलता आया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधान मंत्री थे, तब Nehruvian socialism की बड़ी चर्चा चलती थी और socialism के होते हुए कई सारे नियंत्रण पर आधारित अर्थ-व्यवस्था को भी हमने स्वीकार किया था। हम जानते हैं कि कैसी controlled economy उस समय में थी। बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो एक राष्ट्रीयकरण का दौर आया, वह भी एक दृष्टि से नियंत्रण ही था। उसके बाद श्रीमान् नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने liberalisation, privatising की चर्चा शुरू की और हमने देखा कि वह भी एक तंत्र हमारी अर्थ-व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में भी चला। बाद में United Progressive Alliance की सरकार 2004 में आई, तब उसने सोचा कि कौन-सा नया जुमला आगे चलायें, जिसके आधार पर ...(**व्यवधान**)... जिसके आधार पर एक

लोक-लुभावन राजनीति कर पाएं। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष जी, लोक-लुभावन राजनीति का इनका जो पैमाना था, वह था कि हम एक right based approach लेते हैं, अधिकारों पर आधारित एक व्यवस्था का निर्माण करेंगे। यह देखने में और सुनने में तो अच्छा लगता है, देश का जो गरीब आदमी है, उसको लगता है कि चलो मुझे राइट मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इसलिए इन्होंने एक फूड सिक्योरिटी ऐक्ट बनाया। यह बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं कि उस ऐक्ट के कारण कितनी फूड सिक्योरिटी आई? अगर आई है, तो कितनी आई है, नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई है? फिर इन्होंने राइट टू एजुकेशन को आगे बढ़ाया। यह अच्छा है, इसका कौन विरोध करेगा? मगर क्या केवल राइट देने से राइट मिलता है, इसके बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मूल गंतव्य स्थान जो था, वहां जाने का इरादा तो था ही नहीं। राइट टू एजुकेशन के कारण शिक्षा का सार्वत्रीकरण हो, यह इनकी सोच थी, यह बताते हैं। मैं परिणामों को गिनूंगा, तब सबके ध्यान में आएगा कि इसके परिणाम क्या हुए? हम इसके विरोध में नहीं हैं। हम राइट टू एजुकेशन के विरोध में नहीं हैं। मगर अंधे तरीके से, अगर आप किसी एक विचार सूत्र का आधार लेकर आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, इसके अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। मैं तो अचरज में था, इनकी सरकार थोड़ी सी भी ज्यादा चलती थी, लेकिन इसकी संभावना तो थी नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): आप इनकी-इनकी सरकार कह रहे हैं। इधर तो हम लोग हैं। वे तो उधर बैठे हैं। आप उनको बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: मैडम जी, आप तो साथ में ही हैं। ...(**व्यवधान**)... चलिए, आप छोड़ दीजिए। इतना मन पर मत लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हमारे कांग्रेस के और United Progressive Alliance के सदस्यों की सरकार थोड़ी और अधिक चलती, तो शायद ये एक right to have a smiling face भी ला सकते थे, स्मित हास्य करने का अधिकार। ...(**व्यवधान**)... अब स्मित हास्य करने का अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं होती, आपके चेहरे पर हंसी खिलनी चाहिए, वह तब आती है, जब आप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। परिस्थिति का निर्माण करना इनके बस की बात थी नहीं, इनका इरादा भी नहीं था। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने महज राइट का एक जुमला लगाया और राइट टू एजुकेशन दे दिया - बगैर किसी पूर्व तैयारी के। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? ...(**व्यवधान**)... अब आप विरोध कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... हमारा विरोध बिल्कुल नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: हमारी पूर्व तैयारी थी। ...(**व्यवधान**)... नीरज जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... मेरे कहने का मतलब यह है कि ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप सब्जेक्ट पर आ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा कहना इतना ही है कि बगैर पूर्व तैयारीके किसी कानून को लाया जाता है, तो उसका जो होता है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): आपने बगैर पूर्व तैयारी के नोटबंदी कर दी। ...(**व्यवधान**)...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः मैडम, हम आपको बहुत सुनते हैं, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... आप ज़रा बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Try to learn the art of listening. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप बोलते जाइए।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः आप उनको बताइए। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष जी, उन्हें बताइए कि patience से सुनना भी एक कला होती है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि बगैर पूर्व-तैयारी आप कानून लाए, जिस के कारण आज यह नौबत आ गई कि इस कानून में हमें संशोधन करना पड़ा। अगर ये उसी समय envisage करते तो अच्छा होता। मंत्री जी, अगर इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, तो अच्छा होगा कि यह calculation किस आधार पर किया गया था कि 2015 तक यह सब होगा? क्या हमारे पास इतने trainers थे, क्या इतने शिक्षक हमारे पास थे? उस समय के किस अधिकारी या कौन से मंत्री ने यह चाल चली थी और इस तरह का आकलन किया था और अगर उस में दोष है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज सदन का समय हम इस कानून को बदलने के लिए लगा रहे हैं, यह समय हम क्यों गंवा रहे हैं? क्यों इस पर हमारे समय की लागत लग रही है? महोदय, इस का कारण lack of foresight था यानी दूरदृष्टि का अभाव था और उस वजह से यह परिस्थिति निर्मित हुई है। इस बात को हमारे विपक्ष के मित्रों को स्वीकार करना चाहिए।

मान्यवर, मैं केवल तीन-चार बातें कहना चाहूंगा। यह जो shortage of trained teachers है, इसके पीछे भी अनेक कारण हैं। महोदय, UNESCO के Institute of Statistics की दो साल पहले एक रिपोर्ट आयी है कि दुनियाभर के 74 देशों में शिक्षकों की कमी है और इस में पहला नंबर नाइजीरिया का और दूसरा भारत का है और अगर यह आज की स्थिति के हिसाब से चलता रहा, तो 2030 तक हमें 30 लाख शिक्षकों की कमी महसूस करनी होगी। यह एक बहुत ही डरावना चित्र है, जोकि एक अध्ययन के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। अब सवाल यह है कि शिक्षकों की कमी क्यों होती है? इस के दो-चार महत्वपूर्ण बिंदू हैं। क्या हम बी.एड. और डी.एड. के लिए ऐसे छात्रों को आकर्षित करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं, जिनका कि शिक्षक के पेशे में मन है? क्या बी.एड. या डी.एड. के लिए आने वाले छात्र बीच में dropout हो जाते हैं? क्या ट्रेनिंग करने के बाद और शिक्षक की नौकरी संभालने के बाद भी उनकी निगाहें और कहीं टिकी हुई होती हैं? क्या ऐसा होता है कि उन्हें जाना तो कहीं और होता है, बीच में एक पड़ाव के रूप में शिक्षक की नौकरी कर ली और जितना किया, ठीक है, नहीं तो आगे ही निकलना है? इस तरह के बहुत से सवाल उत्पन्न होते हैं, जिन के कारण शिक्षक का पेशा या vocation of teaching, यह जितना attractive होना चाहिए, ताकि किसी को यह लगना चाहिए कि मैं भी शिक्षक बनूं, उस में हमारी सारी व्यवस्था में दशकों से कुछ-न-कुछ कमियां रहती आयी हैं। मैं मानता हूं कि इस विषय में भी कुछ विचार किए जाने की जरूरत है।

महोदय, जो विषय मैंने शुरू में छेड़ा, उस के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। हम Right to Education लाए, उसका कभी-न-कभी मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि आज यह समय है। आज 13,000 स्कूल्स बंद किए जाने की स्थिति में हैं क्योंकि इस कानून ने अनौपचारिक शिक्षा को एक दृष्टि से गैर-कानूनी शिक्षा माना। महोदय, हमारे देश में अनौपचारिक शिक्षा चलती थी। हमारे देश में ईंट-भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे ऐसे informal schools में पढ़ते थे। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। हमारे यहां गन्ना किसान या गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों के बच्चे भी informal schools में

पढ़ते थे। उन्हें हम "शक्कर विद्यालय" कहते थे, लेकिन आज वे विद्यालय बंद करने पड़े क्योंकि इस कानून के अंदर उन स्कूलों को कोई मान्यता नहीं है। महोदय, और भी प्रावधान हैं, जैसे इन्होंने School Management Committee बनायी। वह कल्पना अच्छी है, मगर School Management Committee में आने वाले अभिभावक क्या उस मानसिकता को रखते हैं? क्या वे वाकई में manage कर पाते हैं या उन्हीं को कोई शिक्षक या मुख्य अध्यापक hoodwink करता है? मैं मानता हूं कि इन सारी स्थितियों के बारे में भी चिंतन करने की जरूरत थी, जो उस समय नहीं किया गया।

महोदय, इस में minority और majority का विवाद चलाया गया है। वह यह है कि इस कानून के जो भी प्रावधान हैं, minorities को उनसे छूट दी गयी है। इसके कारण हर दृष्टि से एक प्रवाह का निर्माण हुआ है और हर कोई अपने को minority कहने लगा है और फिर इस में कोर्ट को कहना पड़ा कि Lingusitic minorities को हम इस के लिए इजाज़त नहीं दे सकते। इस तरह यह कुल मिलाकर बगैर कोई homework और बगैर foresight, एक लोक-लुभावन भावना से प्रेरित होकर लाया गया कानून था। महोदय, यह कानून तो अच्छा था, मगर जो उसमें कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने की चिंता पुरानी सरकार ने नहीं की। आज उनका काम हमारी सरकार को बड़ी शिद्दत से करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं।

महोदय, मैं केवल एक अंतिम विषय बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, अंतिम विषय यह है कि कुल मिलाकर हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में गुरू-शिष्य के संबंधों के बारे में एक बहुत स्वस्थ परम्परा सदियों से चली आ रही है। हमने अपने यहां गुरु-शिष्य संबंधों पर बल दिया है, 'Teacher and taught relationship' आज अगर विदेश में, अमरीका में, ब्रिटेन में कहीं स्कूली व्यवस्था चरमरा सी गई है, तो उसका कारण है कि वहां पर 'Teacher-taught relationship' जितना स्वस्थ होना चाहिए, वह वहां नहीं है। मैं मानता हूं कि इसके लिए एक टीचर की भी mentoring होना जरूरी है। टीचर को स्वयं एक mentor होने की आवश्यकता है और टीचर के लिए भी एक mentorship की आवश्यकता है, जो आज के इस कानून के परिवेश में शायद होना बड़ा मुश्किल सा हो गया है, इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मैंने एक महत्वपूर्ण बिन्दू कहा है कि जो informailty है, हमारे प्रधान मंत्री जी गुजरात में मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में शिक्षा का एक अभियान चलाया था कि हर कोई शिक्षक दिवस पर या किसी एक दिन स्कूल में जाए और एक किताब पढ़ाए, तो एक पढ़ने का culture बने। हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग यह अपेक्षा करते हैं कि उनको भी पढ़ाने का एक छोटा सा अवसर मिले। ऐसे कई लोग पढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं मगर कानून जिस पद्धति से बनाया गया है, यह जो informality है, अनौपचारिकता है, मैं मानता हूं कि उस पर एक कुठाराघात है, जाने-अनजाने में ही सही, मगर बगैर सोच के कारण इस कानून के माध्यम से हुआ है, मैं मानता हूं कि हमें इससे निजात पाना बहुत आवश्यक है।

महोदय, आखिरकार शिक्षक और छात्रों के संबंध और उन संबंधों की ताकत पर ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का यह केन्द्र बिन्दू रहा है। हम जानते हैं कि कबीर के भजन को बेगम आबिदा परवीन ने गाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "साहिब मिले सबूरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में।" मतलब साहिब यानी जो mentor है, भगवान होगा, कोई और होगा अथवा शिक्षक भी होगा, जब वह सबूरी में मिलता है, केवल clock hours के हिसाब से नहीं, जब वह सबूरी से मिलता है, जब interaction बढ़ता है, जब एक रिश्ता निर्मित होता है, जब mentorship

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

खिलती है, तब जाकर छात्र और शिक्षक संबंधों के आधार पर सच्ची ज्ञानार्जन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मैं मानता हूं कि आगे चलकर कानून में इसकी समीक्षा हो। इसमें जो भी कमियां लाई गई थीं, उनके कारण उस समय इसमें लोक-लुभावन और सभी चीज़ों का एक प्रभाव था, उनको क्रमशः हम दूर करने की कोशिश करें, मगर शुरू में निश्चित रूप से यह करना आवश्यक था। माननीय शिक्षा मंत्री ने सही दिशा में एक आवश्यक कदम उठाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और शिक्षा मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही सीमित उद्देश्य के साथ पेश किया है। इसकी भावना भी अच्छी है और इससे ना-इत्तेफाकी रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है तथा इस बिल का जो उद्देश्य है, आज उसकी आवश्यकता भी है। मैं समझता हूं कि हम सबको इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बिल पर अपनी बात रखते हुए, किसी को कोई राजनीति से प्रेरित वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने दिया है। जो काम अच्छा है, वह अच्छा है। आज अगर मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, तो उन्होंने यह एक अच्छा काम किया है। यदि मैं कहूं कि दो साल के अंदर भी तमाम गैर-प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं दे पाओगे या जो infrastructure अभी मंत्री जी ने इस बिल की प्रस्तावना रखते हुए बताया है, तो मैं कहूं कि वह infrastructure ना-काफी है...। यह कहना कि यह और विकसित होना चाहिए, और वृहद् होना चाहिए, राजनीति से प्रेरित वक्तव्य होगा। मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और हम सभी को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की बदकिस्मती कहिए या परिस्थितियाँ कहिए कि आज शिक्षा का, खास तौर से प्राथमिक शिक्षा का जो हाल है, उस पर सिवाय आँसू टपकाने के मुझे और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता है। इसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वे प्रयास कोई भी करे, हमें उन प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है, मैं उस पर यही कहूंगा कि हम इस बिल का सही उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब प्राथमिक शिक्षा का और ज्यादा बेहतर करें, देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकें, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसे हम क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं, उस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दे सकें।

उपसभाध्यक्ष जी, हमें इसके लिए कई काम करने होंगे। हमें सबसे पहला काम तो यह करना होगा कि हम यह समझें कि अध्यापक को हम अध्यापक समझते हैं या हमने उसे हर मर्ज़ की दवा बना रखा है? प्राथमिक शिक्षा में जो अध्यापक लगे हुए हैं, जो अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, आज उनके पास कितने काम हैं? वोट बनाने से लेकर वोट गिनवाना और वोट डलवाना भी उनका काम है।

सरकार ने आधार कार्ड से लिंक करने का एक अभियान हमारे यहाँ चलाया हुआ है। यह अभियान अच्छा है, गलत है या बुरा है, वह बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन उस अभियान में, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे शिक्षक लगे हुए हैं। राशन कार्डों की कहूं, तो अब आने वाले दिनों में राशन नहीं दिया जायेगा, बल्कि बतौर सब्सिडी व्यक्ति के खाते में सीधे धन पहुंचा दिया जाएगा। लिहाजा राशन कार्ड को लिंक करने का काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में, सरकार ने अभी पिछले दो महीने पहले ही यह आदेश दिया है कि इस काम में भी शिक्षकों को लगाओ। जब जनगणना होती है, तब उसमें शिक्षक लगते हैं, पशुगणना होती है, तब उसमें शिक्षकों को लगाया जाता है। पढ़ाने के कार्य, अध्यापन

कार्य के अलावा करीब तीस, पैंतीस कार्य ऐसे हैं, जिनमें प्राथमिक शिक्षकों को लगाया जाता है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर हम इस प्रकार से शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि वे पढ़ाई के लिए कम वक्त देंगे और बाकी कामों में ज्यादा वक्त देंगे, तो शाय हम प्राथमिक शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसके कारण सबको शिक्षा देने का, हर बच्चे को शिक्षित करने का हमारा जो लक्ष्य है, उसको पाने में हम निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे, इसलिए शिक्षकों पर जो अतिरिक्त भार है, उस अतिरिक्त भार को काम करना चाहिए और उन्हें एक्सक्लुसिवली पढ़ाई के काम में ही लगाना चाहिए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ यह बिल लाया गया है, वह फलीभूत होना चाहिए! ग़ैर प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से – अभी उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया के जरिये भी आप लोगों तक, सदन के सभी साथियों तक और सदन के सभाध्यक्ष जी तक खबरें पहुंची होंगी कि आज उत्तर प्रदेश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ पिछले 18, 19 सालों से विद्यालयों में जो लोग शिक्षा मित्र की हैसियत से पढ़ा रहे थे, अध्यापक कार्य को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें 2014 में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्व शिक्षक का दर्जा दिया था, जिनकी संख्या कम नहीं है, जिनकी संख्या 1,72,000 है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से ये 1,72,000 प्राथमिक शिक्षक आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हैं। आंदोलन चल रहा है। वे कहते हैं कि हमने बीस साल पढ़ाया है और जो अनट्रेंड टीचर्स को ट्रेंड करने की सरकार की नीति है, उसके तहत उन सभी शिक्षा-मित्रों को, जिनकी संख्या एक लाख बहत्तर हजार है, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बीटीसी की ट्रेनिंग का इंतजाम किया था, उससे उनको बीटीसी करवाया, यानी वे ट्रेंड हो गए और फिर बतौर शिक्षक उनका समायोजन किया गया था। पिछले तीन सालों से ये पूरे तरीके से विद्यालयों में पढ़ा रहे थे।

महोदय, उत्तर प्रदेश में जब ये शिक्षा-मित्र नहीं थे, तब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 60 प्रतिशत विद्यालय बगैर शिक्षकों के थे। बहुत से विद्यालयों पर ताले लगे हुए थे, गांव में शिक्षा का कोई माहौल नहीं था और जो मिड-डे मील जाता था, वह मिड-डे मील भी अधिकारियों में बंदरबांट हो जाता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री बने, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की इस समस्या को, इस मसले को, जो उनकी कमी थी, उसको लिया और शिक्षा-मित्रों की भर्ती की। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलते-फिरते लोगों को शिक्षा-मित्र नहीं बनाया गया था। अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने चुनाव-प्रचार के दौरान कहा कि इन्होंने अपने-अपने लोगों को शिक्षा-मित्र बनाकर नौकरी दे दी है और यह तो बहुत गलत किया है, जबकि शिक्षा-मित्र के लिए गांवों के अंदर जितने आवेदक थे, मेरिट के आधार पर इनका चयन हुआ था। जब वे सब शिक्षा-मित्र अध्यापक हो गए, तो जैसी हमारे देश की एक परंपरा सी चल गई है कि कोई भी अच्छा काम हो तो उसको चुनौती जरूर दे दो, तो कुछ लोग कोर्ट में चले गए। उन्होंने वहां कहा कि साहब, ये पढ़ा ही नहीं सकते, इन्हें पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। भारत सरकार का कोई नियम बन कर आया कि एक टेस्ट, टीईटी का टेस्ट, टीचर्स एलिजिबिलिटी का टेस्ट, उनको पास करना जरूरी है। शिक्षा-मित्र बीस साल पुराने लगे हुए हैं और यह टेस्ट का नियम अभी दो साल पहले बना है। उन सभी शिक्षा-मित्रों को उस नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया और उनको एक दिन के अंदर सड़क पर ला दिया। आज तक 23 शिक्षा-मित्र आत्महत्या कर चुके हैं और बाकी सब सड़कों पर रो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जगह-जगह जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं। चूंकि शिक्षा अकेले राज्य का विषय नहीं है, शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में आता है, इसलिए प्रदेश सरकार

[श्री जावेद अली खान]

का भी दायित्व बनता है और केन्द्र सरकार का भी दायित्व बनता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस गंभीर मसले पर, जिस मसले को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा-मित्र दो-चार हो रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप करें और उनके लिए रास्ता निकालें। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से स्कूलों में अभी भी टीचर्स की कमी है, जिनको भरने का इंतजाम आप करें। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं पार्टी से ओनली वन स्पीकर हूँ।

† **جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش) :** مانّنے اپ سبھا ادھیکش جی، مانو سنسادھن وکاس منتری جی نے جو یہ بل پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سیمت ادّیشئے کے ساتھہ پیش کیا ہے۔ اس کی بھاونا بھی اچھی ہے اور اس سے نااتفاقی رکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اور اس بل کا جو ادّیشئے ہے، آج اس کو ضرورت بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بل کا سمرتھن کرنا چاہئے۔ میرے خیال سے اس بل پر اپنی بات رکھتے ہوئے، کسی کو کوئی راجنیتی سے پریرت وکتوّے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میرے پچھلے وکتا نے دیا ہے۔ جو کام اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ آج اگر منتری جی نے یہ ودھیک پیش کیا ہے، تو انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ دو سال کے اندر بھی تمام غیر-پرشکشت ادھیاپکوں کو پرشکشن نہیں دے پاؤگے یا جو انفرااسٹرکچر ابھی منتری جی نے اس بل کی پرستاونا رکھتے ہوئے بتایا، تو میں کہوں کہ وہ انفرااسٹرکچر نا کافی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اور وکست ہونا چاہئے، اور ورہد ہونا چاہئے، راجنیتی سے پریرت وکتوّے ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم سبھی کو اس بل کا سمرتھن کرنا چاہئے۔ میں یہاں پر اپنی پارٹی کی طرف سے اس کا سمرتھن کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے دیش کی بدقسمتی کہئے یا پرستتھیاں کہئے کہ آج شکشا کا، خاص طور سے پراتھمک شکشا کا جو حال ہے، اس پر سوائے آنسو ٹپکانے کے مجھے اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے لئے جو پریاس کئے جاتے ہیں، وہ پریاس کوئی بھی کرے، ہمیں ان پریاسوں کی سراہنا کرنی چاہئے، ان کا سواگت کرنا چاہئے۔ پراتھمک شکشا کی جو حالت ہے، میں اس پر یہی کہوں گا کہ ہم اس بل کا صحیح ادّیشئے تبھی حاصل کر سکتے ہیں، جب پراتھمک شکشا کو اور زیادہ بہتر کریں، دیش کے ہر بچے کو پراتھمک شکشا، گن-وتّا-پورن شکشا دے سکیں، جس کے اندر کوالٹی ہو، جسے ہم کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں، اس طرح کی شکشا بچوں کو دے سکیں۔

اپ سبھا ادھیکش جی، ہمیں اس کے لئے کئی کام کرنے ہوں گے۔ ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ادھیاپک کو ہم ادھیاپک سمجھتے ہیں یا ہم نے اسے ہر مرض کی دوا بنا رکھا ہے؟ پراتھمک شکشا میں جو ادھیاپک لگے ہوئے ہیں، جو

†Transliteration in Urdu script.

ادھیاپک، ادھیاپن کا کام کر رہے ہیں، آج ان کے پاس کتنے کام ہیں؟ ووٹ بنانے سے لے کے ووٹ گنوانا اور ووٹ ڈلوانا بھی ان کا کام ہے۔

سرکار نے آدھار کارڈ سے لنک کرنے کا ایک ابھیان ہمارے یہاں چلایا ہوا ہے۔ یہ ابھیان اچھا ہے، غلط ہے یا برا ہے، وہ بحث کا الگ مدّعا ہے، لیکن اس ابھیان میں، اتر پردیش کے اندر ہمارے شکشک لگے ہوئے ہیں۔ راشن کارڈوں کی کہوں، تو اب آنے والے دنوں میں راشن نہیں دیا جائے گا، بلکہ بطور سبسڈی آدمی کے کھاتے میں سیدھے دھن پہنچا دیا جائے گا۔ لہذا راش کارڈ کو لنک کرنے کا کام بھی چل رہا ہے۔ اتّر پردیش میں، سرکار نے ابھی پچھلے دو مہینے پہلے ہی یہ آدیش دیا ہے کہ اس کام میں بھی شکشکوں کو لگاؤ۔ جب جن۔گننا ہوتی ہے، تب اس میں شکشک لگتے ہیں، پشو۔گننا ہوتی ہے، تب اس میں شکشکوں کو لگایا جاتا ہے۔ پڑھانے کا کام، ادھیاپن کے کام کے علاوہ قریب تیس، پینتیس کام ایسے ہیں، جن میں پراتھمک شکشکوں کو لگا یا جاتا ہے۔

مانئے اپ سبھا ادھیکش جی، میں منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے شکشکوں کی ذمہ داری طے کریں گے کہ وہ پڑھائی کے لئے کم وقت دیں گے اور باقی کاموں میں زیادہ وقت دیں گے، تو شاید ہم پراتھمک شکشا کے ساتھ نیائے نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے سب کو شکشا دینے کا، ہر بچے کو شکشت کرنے کا ہمارا جو لکشئے ہے، اس کو پانے میں ہم نشچت روپ سے پچھڑ جائیں گے، اس لئے شکشوں پر جو اضافی بوجھ ہے، اس اضافی بوجھ کو کم کرنا چاہیئے اور انہیں ایکسکلوسئیولی پڑھائی کےکام میں ہی لگانا چاہیئے۔

میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے ساتھ یہ بل لایا گیا ہے، وہ فلیبھوت ہونا چاہیئے۔ غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دینے کے مقصد سے۔ ابھی اترپردیش کے بارے میں آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، میڈیا کے ذریعہ بھی آپ لوگوں تک، سدن کے سبھی ساتھیوں تک اور سدن کے سبھا۔ادھیکش جی تک خبریں

[श्री जावेद अली खान]

پہنچی ہونگی کہ آج اترپردیش ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے، جہاں پچھلے اٹھارہ انیس سالوں س اسکولوں میں جو لوگ شکشا متر کی حیثیت سے پڑھارہے ہیں، ادھیاپن کارنیے کو انجام دے رہے تھے، جنہیں 2014 میں، اترپردیش کی سرکار نے مکمل استاد کا درجہ دیا تھا، جن کی تعداد کم نہیں ہے، جن کی تعداد ہے ایک لاکھہ بہتّر ہزار ہے، سپریم کورٹ کے ایک آدیش سے یہ ایک لاکھہ بہتّر ہزار پراتھمک شِکشک آج اترپردیش کی سڑکوں پر ہیں۔

آندولن چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیس سال پڑھایا ہے اور جو ان۔ٹرینڈ ٹیچرس کو ٹرینڈ کرنے کی سرکار کی نیتی ہے، اس کے تحت ان سبھی شکشا متروں کو، جن کی تعداد ایک لاکھہ بہتّر ہزار ہے، ان کے لئے اتر پردیش سرکار نے جو بی۔ٹی۔سی۔ کی ٹریننگ کا انتظام کیا تھا، اس سے ان کو بی۔ٹی۔سی۔ کروایا ہے، یعنی وہ ٹرینڈ ہو گئے ہیں اور پھر بطور شکشک ان کا سمایوجن کیا گیا تھا۔ پچھلے تین سالوں سے یہ پورے طریقے سے ودھیالیوں میں پڑھا رہے تھے۔

مہودے، اتّر پردیش میں جب یہ شکشا متر نہیں تھے، تب اتّر پردیش کے گرامین علاقوں میں قریب ساٹھہ فیصد ودھیالے بغیر شکشکوں کے تھے۔ بہت سے ودھیالیوں پر تالے لگے ہوئے تھے، گاؤں میں شکشا کا کوئی ماحول نہیں تھا اور جو مڈ۔ڈے میل جاتا تھا، وہ مڈ۔ڈے میل بھی ادھیکاریوں میں بندر بانٹ ہو جاتا تھا، لیکن جب اتر پردیش میں اکھیلیش یادو جی مکھیہ منتری بنے، تو انہوں نے پراتھمکتا کے آدھار پر شکشکوں کی اس سمسیہ کو، اس مسئلے کو، جو ان کمی تھی، اس کو لیا اور شکشا متروں کی بھرتی کی۔

مانئے منتری جی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چلتے پھرتے لوگوں کو شکشا متر نہیں بنایا گیا تھا۔ اب جو اتر پردیش کے اندر ستّہ دھاری لوگ ہیں، انہوں نے چناؤ پرچار کے دوران کہا کہ انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو شکشا متر بناکر نوکری دے دی ہے اور

یہ تو بہت غلط کیا ہے، جب کہ شکشا متر کے لئے گاؤں کے اندر جتنے آویدک تھے، میرٹ کے آدھار پر ان کا چئن ہوا تھا. جب وہ سب شکشا متر ادھیاپک ہو گئے، تو جیسے ہمارے دیش کی ایک پرمپرا سی چل گئی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس کو چنوتی ضرور دے دو، تو کچھ لوگ کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے وہاں کہا کہ صاحب، یہ پڑھا ہی نہیں سکتے، انہیں پڑھانے کا ادھیکار ہی نہیں ہے. بھارت سرکار کا کوئی قانون بن کر آیا کہ ایک اسٹیٹ، ٹی.ای.ٹی. کا ٹیسٹ، ٹیچرس ایلجبلٹی ٹیسٹ، اس کو پاس کرنا ضروری ہے. شکشا متر بیس سال پرانے لگے ہونے ہیں اور یہ ٹیسٹ کا قانون ابھی دو سال پہلے بنا ہے. ان سبھی شکشا مترون کو اس قانون کے تحت سپریم کورٹ نے اپنا ڈسیزن دیا اور ان کو ایک دن کے اندر سڑک پر لا دیا. آج تک 23 شکشا متر خودکشی کر چکے ہیں وار باقی سب سڑکوں پر رو رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جگہ جگہ ضلع مکھیالیوں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ شکشا اکیلے راجیہ کا وشئے نہیں ہے، شکشا کا وشئے سم-ورتی سوچی میں آتا ہے، اس لئے پردیش سرکار کا بھی دائتو بنتا ہے اور کیندر سرکار کا بھی دائتو بنتا ہے. میں مانئے منتری جی سے یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ اس گمبھیر مسئلے پر، جس مسئلے کو لے کر اتر پردیش کے اندر شکشا متر دو چار ہو رہے ہیں، اس میں ہستکشیپ کریں اور ان کے لئے کوئی راستہ نکالیں. آج ہمارے اتر پردیش کے اندر بہت سے اسکولوں میں ابھی بھی ٹیچرس کی کمی ہے، جن کو بھرنے کا انتظام آپ کریں ..(وقت کی گھنٹی)... سر، میں پارٹی سے اونلی-ون اسپیکر ہوں.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपकी पार्टी का जितना टाइम है, वह पूरा हो चुका है।

श्री जावेद अली खान: ठीक है, सर। वैसे भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने तो बिल का समर्थन कर दिया है, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, पूरी शिक्षा-प्रणाली के दोष नहीं गिनाने हैं, न कोई तरह-तरह के बनावटी इल्जाम, मनगढंत इल्जाम लगाने हैं। मैंने इस बिल का समर्थन किया है और माननीय मंत्री जी से यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए वहां की जो पूर्व सरकार ने शिक्षा-मित्रों को लाकर राहत दी थी, सुविधा दी थी और उनको जो स्थान दिया था, शिक्षकों के रूप में जिनका समयोजन किया था, उस व्यवस्था को जारी रखने के लिए अगर अदालत के अंदर पक्ष भी बनना पड़े तो केन्द्र सरकार को पक्ष बनना चाहिए और अगर कोई नियम या कानून लाना हो, या उन शिक्षा-मित्रों को बहाल करवाने की दिशा में जो भी कदम उठाना पड़े, वह सरकार को उठाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

† **جناب جاوید علی خان :** ٹھیک ہے، سر۔ ویسے بھی میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ میں نے تو بل کا سمرتھن کر دیا ہے۔ مجھے کوئی راجنیتی نہیں کرنی ہے، پوری شکشا پرنالی کے دوش نہیں گنانے ہیں، نہ کوئی طرح طرح کے بناوٹی الزام، من گھڑت الزام لگانے ہیں۔ میں نے اس بل کا سمرتھن کیا ہے اور مانّنے منتری جی سے یہ مانگ کی ہے کہ اتّر پردیش میں شکشکوں کی کمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں کی جو سابق سرکار نے شکشا متروں کو لاکر راحت دی تھی، سویدھا دی تھی اور ان کو جو استھان دیا تھا، شکشکوں کے روپ میں جن کا سمایوجن کیا تھا، اس ویوستھا کو جاری رکھنے کے لئے اگر عدالت کے اندر پکش بھی بننا پڑے تو کیندر سرکار کو پکش بننا چاہئے اور اگر کوئی نیم یا قانون لانا ہو، یا ان شکشا متروں کو بحال کروانے کی دشا میں جو بھی قدم اٹھانا پڑے، وہ سرکار کو اٹھانا چاہئے۔ بہت بہت دھنیواد۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Next speaker is Mr. A.K. Selvaaraj.

SHRI A.K. SELVARAJ (Tamil Nadu): Respected Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on an important Bill concerning the future of the millions of students of our country. I am also happy to say that I am allowed to speak on a subject which is very close to the heart of our beloved leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma; and I dedicate this speech to my beloved leader, Dr. Amma.

†Transliteration in Urdu script.

The objectives of the Bill are to provide an opportunity to untrained and unqualified teachers to acquire minimum qualification. It is very pity to note that out of total number of 66.41 lakh teachers at the elementary level, 11 lakhs are still untrained. Better trained teachers would mean an improvement in the learning outcome of children. Quality improvement will not happen unless the foundation, principles, content, and pattern of pre and in-service training of teachers are relooked at and changed. It is said that just knowing a subject or being a graduate, is not sufficient qualification to become an elementary school teacher. One has to be trained in understanding the learning process of children, their diversity, and one has to develop necessary teaching skills under trained supervision.

The Government's budget for the Sarva Shiksha Abhiyan, has increased from ₹ 12,825 crore in 2009-10 to ₹ 22,500 crore in 2016-17. Around 3.5 lakh schools have been opened in the last one decade and 99 per cent of India's rural population now has a primary school within a one kilometer radius. India has the largest number of out-of-school children in the world. Sir, school education for children aged between six and fourteen years is a fundamental right in India. However, from 2010, after the Act was passed, it has faced severe challenges in its proper implementation. Even the budget allocation for the year 2017-18 has been very disappointing for the education sector. The low increase in the Sarva Shiksha Abhiyan of ₹ 1,000 crore is not going to help in any way to implement the RTE Act meaningfully. Even after six years of implementation of the RTE Act, only 9.5 per cent schools have been made RTE- compliant across the country. It has been established that millions of children are still out of schools, and that thousands of additional schools are yet to be built, while lakhs of teachers are yet to the recruited, and trained. Low allocation is hampering the quality of education in Government schools, which have teachers vacancy of more than five lakh. Ten per cent of the schools are single teacher, and 30 per cent of schools are without functional toilets for girls, and 20 per cent of it still lack safe drinking water.

Now I come to some issues faced by the people in rural areas where schools were not there within a radius of one kilometer as per the RTE Act. The schools in private sector were not willing to accommodate the students from below poverty line, and even if they provide admission, they insist the students to pay the entire amount of fee at one time, alleging that there is a long delay in releasing fund under the RTE Act to these schools. The State Government of Tamil Nadu has been implementing Section 12(1)(c) of the Act in true letter and spirit. For the admissions made in private schools in 2013-14

[Shri A.K. Selvaraj]

4.00 P.M.

and 2014-15, a reimbursement of ₹ 97.05 crore has already been made to private schools by the State Government, and this amount was claimed in 2016-17 under the Sarva Shiksha Abhiyan plan. An amount of ₹ 18 lakhs has been approved by the Government for reimbursement.

Despite non-release of funds by the Government of India, the State Government continued implementation of the Act in the years 2015-16 and 2016-17, and additionally, 1,92,317 number of children have been admitted in private schools under the 25 per cent reservation. The private schools would have to be reimbursed an amount of ₹ 310.70 crores for the children admitted for the years 2015-16 and 2016-17.

The State Government would have to be reimbursed a total amount of ₹ 407.75 crores for 3, 28,910 children under SSA. The Government under the dynamic leadership of our hon. Amma was in the forefront in the education segment too, and our beloved Amma had ensured the growth of education in the State by providing all grants and tools for the students from books to laptop and free schools bus passes to bicycles and these initiatives led to a drastic reduction in the dropout of school children. Many states were inspired of it and implemented it in their respective States. ...*(Time-bell rings)*... At the end of my speech, I would like to urge the Government to release a total grant under SSA of ₹1340.89 crore and a sum of ₹ 545.05 crore under Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan for the years 2015-16 and 2016-17 and to link again the model school programme with Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan as delinking will affect the children who are already enrolled in the model schools. The Government also release funds claimed by the State Government of Tamil Nadu for the Pre and Post-Matric Scholarship Schemes, so as to motivate the people belonging to downtrodden communities, as demanded by our hon. Chief Minister, Thiru Edappadi Palaniswami. With this, I conclude and support the Bill.

Thank you, Sir.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, we support this Bill. Basically in one sentence what is this — it is giving longer time for teachers to be trained. So, 2015 it has taken retrospectively, so four years to that, it takes up to 2019. I would have been the happiest standing here today in 2015 if the Minister had brought this Bill in 2015, allowed for four years, it would have given a better chance. No politics with education when it comes to Bengal, so I want to make some observations not only on this Bill but beyond

this because we have a chance to speak on this Right to Education. So, the first thing is, I hope we don't have to come back here in 2019 to again bring an amendment to this Bill to ask for another two years. The second option obviously could be that you leave that option to State Governments. Sir, the Bill is not the issue or the Right to Education Act is not the issue. I was a little disappointed because Vinayji normally stays above politics but today he got into the politics of it. I am not here to get into the politics of it. I think ideation and implementation, where we have all failed. We have collectively failed as parliamentarians, as parents, as teachers, as educationists. We have had a Bill, so let us focus where we have not implemented the Bill very well. Sir, if we had implemented the Bill very well, today if you look at the survey which has been done, class V student is actually at the level of class II student. Three out of five students in the III Std., they cannot do a basic subtraction, four out of five students cannot do division. So, these are the collective failures. So, now the issue here is the teachers. In my State in West Bengal the extra time the Minister is giving, we have been very proactive with this. We have appointed eighty thousand teachers in the last six years– about fifty thousand in the primary and about twenty-eight in the secondary. So, the things are going on well there, Sir. But, I wish to flag the first point about the time which you have given and it is two years. I have to make three more basic points on the Right to Education. Sir, history is a great learner. All my friends here, what were their views, this is important here; After the Emergency of 1975 till 1976, education was a State Subject. It was only in 1976– you come to your own conclusions– that it was put on to the Concurrent List. In that spirit I hope that this Government, when they view education, is viewing it as originally in the State List, now it got slipped into the Concurrent List. Sir, so, the States sometimes need to have independence to take calls on RTE. Let me give you one example. It is the detention policy.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): The 1976 Amendment, bringing education under the Concurrent List, was not amended in 1978. So, there has been a continuity in thinking on bringing education into the Concurrent List. Let's get our facts correct.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I didn't mean to say it in that way. I was just giving you a fact that in 1975, 1976, 1978... I am not trying to make any political point here. That is not my purpose. I was just saying that the bigger point here is on the Concurrent List. Let's take a view, for example, on detention policy. There is a policy on detention. My State's policy is very, very clear. We have written to the Minister. We do not believe in automatic promotion. Just saying that there will be no detention is not the answer. We

[Shri Derek O'brien]

don't need to deprive anybody. That does not mean that we will deprive the students. If the boys or girls are getting detained, we have to have special classes, we have to have special inputs and then bring them up to a level. So, our point on detention is very, very clear. Sir, I would like to thank the Minister for clarifying one thing again because that causes a lot of concern and sometimes the media also has to be a little more responsible. He did clarify later and I know he did, but I want to put it on record here that NCERT books will be compulsory in the CBSE curriculum. Now, that is again impeding on States' rights, but the Minister did clarify and I have no issues with that, Sir. Sir, in fact, these exam boards, be it the NEET, where CBSE made a complete mess of the NEET — or now at least till two days ago I was hearing that the ICSE Board were trying to give examinations for class V students and class VIII students — Sir, this goes against the basic principles of this Act because Section 30 of this Act clearly states that you cannot have examinations from class V to VIII. So, this is where the States have a role to play. Sir, we have looked at it from different views. Sir, I will take one or two minutes. I know the favourite for boys or girls, for all of us is the bashing private schools. As Vinay*ji* said quite correctly, the minority schools, quite rightly and correctly, have been kept away. Sir, we call them minority schools, but actually they are the majority schools. They may be run by a minority community, say the Christian schools, but most of the boys and girls who go there, including so many of us in this House, have received majority education. I want to dwell a little, Sir, on the private schools, not to make a point for the private schools, but this is where I firmly believe, passionately believe, that to make this work we have to make it work together. Now, what happens? I have got some suggestions. I don't have the answer to all of them, but maybe the Minister can meet the stakeholders and look for these suggestions. The first suggestion is, what happens in a school? I have got 400 students in class one. So, 100 have to be as per RTE now and 300 regular. When 100 students are not taken, Sir, what will you do? Those seats go empty. I am not suggesting that you ask the schools to fill it up with regular students. I say we need to talk to schools because private schools have to take this up as a responsibility. Sir, the private school, as per the Act, neighbourhood students are what they can take. These are serious points beyond any level of politics.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, about the neighbourhood schools, this is sometimes what the private schools are facing. Number one, the private schools have to look at this as a Corporate Social Responsibility. They have to go out and look for students. Just

putting up a notice in the school saying 25 per cent is reserved वगैरह-वगैरह will not be sufficient. I suggest humbly to the private schools to please go out pro-actively and look for students. Sir, the third point is, there are local officers, and I say this with responsibility, who are giving certificates, having children admitted to the schools and then taking plush money from the banks. Sir, this is not acceptable. The fourth point, Sir, is uniforms. When the private schools are taking these students, I know the Act says that they don't need uniforms, but once they don't have uniforms they stand out. I don't expect them to pay for the uniforms. I appeal to the private schools to please pay for those uniforms, make them look like the rest of you. Sir, the last and the most serious point, which I don't think that we are going to finish it here in a discussion, is this. There are serious social, psychological issues of getting boys and girls from different economic backgrounds to sit together in a school. I don't have the answer. But, I think, we need to seriously discuss and debate this and not to make any political points, because, at the end of it all, for the Right to Education to be successful — does not matter whether you are sitting this side or that side — we have to be pragmatic. I know this Government loves to use different acronyms. So, I have got one for them today. We need to do STEPP. Sir, 'S' means 'schools' have a role to play. 'T' means 'teachers' have a role to play. 'E' 'educationists' or *maliks* of a school have a role to play. 'PP' means 'Parliament' and 'parents' have a role to play. I would appeal to the hon. Minister that if you can get these five stakeholders on board, we can change the lives of children in India. Thank you.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this Derek? As soon as I came, you stopped!

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, thank you. That is what I was suggesting. Sir, you just give me ten seconds. It is about the period. We will come back here in 2019. You make it 2021 to make it realistic. Thank you.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I welcome and support the Bill — The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017. This Bill is a continuation of the historic legislation that we had passed.

It has been clearly stated in the Financial Memorandum that Clause (2) of the Bill provides for insertion of a new Sub-Section (2) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, so as to provide that every teacher appointed

[Shrimati Jharna Das Baidya]

or in position as on 31st March, 2015, who does not possess minimum qualifications as laid down under Sub-Section (1) of the said section, shall acquire such minimum qualifications within a period of four years. This is the crux of this Amendment Bill.

Sir, out of 66.41 lakh elementary teachers, 11 lakhs — 5 lakhs in Government schools and 6 lakhs in private schools — are untrained. They should have got trained by 31st March, 2015. The Bill gives time, I hope, up to 31st March, 2021. Their training is very important to raise the quality of teaching. But, many of them are SCs/STs and OBCs. So, the Government has to help them. But, if you look at the funds allocated in 2017-18 for SSA, it has an increase of only ₹ 1,000 crores. This will not help to improve quality of elementary education.

Sir, a higher allocation of resources for school education, from primary level to secondary level, was expected. But, after a year of long waiting, school education has been totally neglected in the Budget. The Budget has ignored the effective implementation of the Right to Education Act and a meager increase for Sarva Shiksha Abhiyan has been made in the Budget —only ₹ 1,000 crore is not going to help, in any way, to implement the Right to Education Act. Sir, we have seen the record of the Left Front Government in many areas of development, particularly in human development. It is no less than outstanding. The literacy rate in the State of Tripura has reached to 97 per cent, which is among the highest in the country. The female literacy rate is 95.71 per cent. With huge expansion of school education, free text books, free studies up to the college level, Tripura has virtually universalized education up to secondary stage.

But, unfortunately, it has become a mechanism or a way of making money. It should not be considered as an industry. It should be considered as an area where you contribute. The hon. Minister has brought forward this Bill, and we all support it. But the Government should take due care of the areas, such as, mid-day meal, infrastructure issues, etc. It is not only the responsibility of the Central Government but the State Governments should also come forward and contribute.

What I have found is, the Government must also inform this House as to how many unqualified teachers were barred from teaching since 2015 and as to how it has ensured that they do not sneak into schools to teach on *ad hoc* basis. ...*(Time-bell rings)*... Just one more minute, Sir.

Therefore, I would like to submit that you cannot control all these things at the Union Government level. Allow the respective States to take decisions, especially as this

is the right-based law. For any change, which you want to make in the law, you have to come to Parliament; you have to get it sanctioned. For the right-based law, why can't we allow or empower the respective States to do this?

With these words, I support the Bill.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, before speaking anything, I would like to say that my party, Biju Janata Dal, supports this Bill. We are happy that the Ministry has taken a very dynamic step to build the nation — a proper nation, a strong nation.

Coming to my views on this Bill, we all know that education improves ones' knowledge and general awareness. And, thereby, that individual's contribution to the society and nation-building becomes more authentic, more qualitative, and more meaningful.

Initially, I would like to say that the right of children to free and compulsory education not only entitles him to free and compulsory education, but also entitles him to compulsory admission, attendance, and completion of basic and elementary education.

This Act was passed in Parliament in 2009 and came into effect from 1st of April, 2010. I have just a small question in my mind. When we talk about one hundred per cent literacy in India, why do we just think of only those children who are between the age of 6 to 14? Why can't we make basic and elementary education compulsory for everyone, barring age-line? Why can't everyone be educated properly, so that we have a proper strong nation, which can think very strongly and very firmly towards development? I am very sorry to say that although the Government is initiating this Bill, Right to Compulsory Education, for the age group of 6 to 14,... if you go around Parliament, within the radius of 5 to 10 kilometers, you will find dozens of children of this age working as labourers and as workers especially at eating outlets. So, will the Government deny this? Will the Government say that I am giving a wrong fact? Sir, you may ask those kids, "बच्चे, तुम बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं तुम्हें free education देने के लिए तैयार हूं। Will you come with me? I will help you to study and to move forward in life." They are so beautifully taught that they immediately say, "Sir, my age is 15, 17 or 18 years or above that." They don't hesitate in telling a lie. Sir, I have raised the same issue, the child labour issue, several times in this House and everyone is aware of that. I feel that unless the Government takes a strong stand on mandatory school attendance of all children below the age group of 16, may be not 18, maybe only then the dream of

[Shri Anubhav Mohanty]

having a 100 per cent literate India can come true or else it will be in dreams. हमारे सबके सपने रह जाएंगे और मोदी जी के सपने भी रह जाएंगे। So, I request the Government to think over it. The other miserable approach of the Government is to somehow make the children clear 8th standard for appearing in the Board. This needs to be recognised, Sir, as this will only increase the data of literate children in the Government records and there will be zero and minimal result of effective compulsory education. Sir, आज किसी नौकरी के लिए, किसी छोटी जॉब के लिए, एक लड़का जब कहीं apply करता है या interview देने जाता है, the minimum required educational qualification is 12th standard pass. Earlier, it was 10th, now it is 10+2 or 12th class. So, why don't you think of making education free and compulsory for all the children till the 12th standard? Why is it only till the age of 14? क्योंकि 6 से 14 साल तक बच्चा आठवीं क्लास तक पढ़ सकता है, पास हो सकता है या कोई knowledge gain कर सकता है, लेकिन नौकरी के लिए, अपनी जीविका अच्छी बनाने के लिए, he has to qualify the 12th class. So, the Government should think over making free and compulsory education till the 12th standard. Also, when I analysed the dropout rates of students from schools, I found that girls are beating boys. It will be a great support for my own Bill that I had introduced in the House last year advocating equal participation by women in governance. I will be really happy to have this. Sir, alongwith encouraging the girl child in education, all the policies concerning education should be made compulsory for the minority institutions also so that the benefit and growth is uniform.

Sir, this Bill deals only with one aspect, and that aspect is relating to the shortage of qualified teachers. Although I have full faith in the hon. Minister, he has been a dynamic Minister till now, but since he has been allocated HRD, I am more excited because I am a young guy coming from Odisha, and I have strong dreams and hopes to see India at a higher place very, very soon. But he has picked up one aspect which has been pending for the last so many years, or, say, at least, for the last three years, which should have been completed by 2013. Sir, I have a question related to this issue. Why did the hon. Minister bring this issue in 2017 and why not before? Can the Government inform this House what happened when the earlier March 31st, 2015 deadline approached? Were those under-qualified teachers banned from teaching? It has been two years since that deadline, and there is some amount of churning that has happened in the education system. Did this churning force certain teachers to get trained as quickly as possible in order to retain their posts? ...*(Time-bell rings)*... Sir, I will conclude in two more minutes. Then, I would second what Mr. Derek O'Brien*ji* said, that States must be given liberty and some powers

to take this forward. I would also like to mention that my Biju Janata Dal colleague in Lok Sabha, Shri Bhartruhari Mahtab, had brought an amendment to the same Bill, but the hon. Minister very wittily ignored it. I don't know why, Sir. If you could give some reply to that amendment and also to my queries, I will be grateful to him. Sir, I will quote him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: At the time of amendments, I will allow you.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, I will finish in two minutes. Sir, I will give the points. In the Bill, Line 12, after 2017, just to add, 'all such extendend period as may be specified by the State Government by notification.' Sir, it is very clear now that the Union Government alone cannot do this properly. So, why can't the Union Government give some power, empower the respective State Governments, to come forward and be a part in making this Bill a successful one? ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, finally, हम एक जगह पर बात करते हैं 'right to free and compulsory education' और दूसरी जगह पर, हम सारे एमपीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए हमें हर साल केवल 10 कोटाज़ मिलते हैं। सर, मैं जब भी घर के बाहर निकलता हूं, तो वहाँ रोज़ 10, 15 या 20 लोगों की भीड़ लगी रहती है और वे लोग मुझसे कहते हैं कि बच्चे को पढ़ने का मौका दे दीजिए, आप हमें कोटा दे दीजिए। But, Sir, who am I to deny them from studying? Who am I to say them 'no'? I am nobody to say them 'no'. I have no right to say them 'no'. सर, एमपी होने के बाद मैंने बहुत-से अच्छे काम कि एहैं,लेकिनसिर्फयहएककारणहै,जिसकेचलतेहोसकताहैमैंबदनामभीहोजाऊँ।आपएक काम कीजिए। ...(**समय की घंटी**)... या तो आप 10 कोटाज़ कैंसल कर दीजिए, एक कोटा भी मत रखिए। ...(**समय की घंटी**)... अगर आप दे रहे हैं, तो give us such powers so that we can really help needy children in getting proper education in proper schools. Thank you very much, Sir.

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): श्रीमान्, मैं अपनी पार्टी की लीडर, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017 पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, शिक्षा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को मान और अपमान का एहसास कराती है। शिक्षा मनुष को आत्मसम्मान ही नहीं देती, उसे निर्भक भी बनाती है और शिक्षा मनुष्य को अंधविश्वास की अँधेरी सुरंग में जाने से रोकती है। मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुजन समाज में समय-समय पर जन्मे जिन सन्तों, गुरुओं और महापुरुषों ने इस देश में प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक और शैक्षणिक गैर-बराबरी को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था, उनमें मुख्य रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज एवं बाबा साहेब अम्बेडकर

[श्री अशोक सिद्धार्थ]

शामिल थे। Mahatma Phule firmly believed that only the axe of education would cut down slowly but surely the trees of ignorance and exploitation. महात्मा ज्योतिबा फुले पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक गैर-बराबरी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सबसे पहले इस देश में स्त्रियों की शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सन् 1848 में पहली बार स्त्रियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। वे पहले ऐसे भारतीय थे, जिन्होंने अपने प्रयास से स्त्रियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। इतना ही नहीं, जिस समाज के लोगों की शिक्षा के लिए स्कूल के दरवाजे खुले नहीं होते थे, जो स्कूल के दरवाजे तक पहुँच नहीं सकते थे, उन लोगों के लिए भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन् 1851 में स्कूल खोलने का काम किया। आज कम्पल्सरी एजुकेशन के संबंध में यह बिल आया है, लेकिन आज से 125 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान सन् 1882 में जब शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन भारत आया था, तो उसके सामने महात्मा ज्योतिबा फुले ने यह माँग रखी थी कि देश में 12 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कम्पल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए। मान्यवर, हम 125 साल के बाद, आज़ादी के 70 साल बाद आज फिर से बच्चों को कम्पलसरी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, जबकि हम सभी लोग और पूरा सदन इस बात से अवगत है कि आज भी इस देश में लाखों स्कूल्स ऐसे हैं, जो केवल एक टीचर से चल रहे हैं। आज भी लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां पर 50-60 बच्चों के स्कूल में एक टीचर है। आज भी टीचर कहीं पल्स पोलियो की ड्यूटी में लगता है, तो कहीं मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की ड्यूटी में लगता है, तो कहीं अन्य कामों में उसका लगा दिया जाता है या स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं में उसको काम पर लगा दिया जाता है। जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज ने - आज हम जो कम्पलसरी एजुकेशन का बिल यहां पर अमेंड करने के लिए लाए हैं, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज ने 1917 में Right to Compulsory Education Bill अपनी रियासत कोल्हापुर में पास किया था। उसके सौ साल बाद हम भारत में यह बिल ला पाए। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम केवल इस तरह के बिल लाएंगे या उन बिल्स को लाने के बाद उनको हकीकत में तब्दील भी करेंगे। इस बिल के उद्देश्य से यह जरूर लगता है कि इक्वेलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी और गारंटी पर जोर दिया गया है, लेकिन केवल जोर देकर के हकीकत में तब्दील होगा कि नहीं होगा, हमें इस बात पर शंका है। मान्यवर, आज तक उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी की लीडर परम आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी के समय में, चाहे उनकी साढ़े चार महीने की सरकार रही हो या छः महीने की रही हो या 15 महीने या पूरे 5 साल की सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा प्राथमिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर बल देने का काम किया था। प्राथमिक शिक्षा पर बल देने के लिए उसमें गुणोत्तर विकास हो, उसके लिए उन्होंने 88,000 बी.टी.सी. प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की थी और ट्रेंड स्टाफ की भर्ती करने का काम किया था। गरीब बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने अपने शासनकाल में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अंतर्गत हाईस्कूल पास बेटी को 25,000 रुपऐ और एक साइकिल के माध्यम से प्रोत्साहित करने का काम किया था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री अशोक सिद्धार्थः मान्यवर, मैं इस बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो आज प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के स्कूल्स हैं, जो इस देश के तमाम औद्योगिक घरानों

द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के बच्चों को या गरीब बच्चों को, चाहे वे जिस समाज से ताल्लुक रखते हों, उनको भी क्या अलग से रिजर्वेशन देने का कोई प्रावधान इस बिल के माध्यम से आगे किया जायेगा? अगर नहीं किया जायेगा तो क्यों नहीं किया जायेगा? मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा का ही माध्यम रहे, यह व्यापार न बने, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Siddharth. Now, Dr. Narendra Jadhav.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Amendment Bill, somewhat reluctantly, even while congratulating the Minister for his efforts.

Sir, the Right of Children to Free and Compulsory Education has been a part of the Directive Principles of State Policy enshrined in the Indian Constitution. It took us as long as 60 years to translate this noble Directive Principle into an Act, from 1950 to 2010. Under the Right to Education Act, 2009, which became operational in 2010, if a State does not have adequate teacher training institutions or sufficient number of qualified teachers, the provision to possess minimum qualifications could be relaxed for a period not exceeding five years, which was up to 31st March, 2015. Now, this Amendment Bill further states that those teachers who do not posses the minimum qualifications as of March 31st, 2015, should acquire the minimum qualifications within a period of four more years, that is, by March 31st, 2019. Apparently, this extension is being given without any punitive action, not even a reprimand. To my mind, such delays are diluting the spirit of one of the finest and fundamental pieces of legislations that we have had.

Sir, while I reluctantly go along with the proposed amendment, I strongly urge the Government not to be so relaxed and accommodative as far as the implementation of this great Act is concerned, in future.

Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Dr. Narendra Jadhav for being brief and to the point. That is how it should be. Shri V. Vijayasai Reddy, you can follow his good example.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Definitely, Sir. Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, for the opportunity you have given me. I rise to support this Bill. However, I have five concerns which I would like to bring, through you, to the

[Shri V. Vijayasai Reddy]

notice of the hon. Minister. The first concern is the need to enhance the teachers' training. Sir, the hon. Minister, while initiating the discussion, has made an observation saying that three lakh teachers have already been trained and the remaining are being trained whose training will be completed shortly. I am not implying to make an allegation against the Minister. But, according to the figures available with me, that observation of the hon. Minister is facutally incorrect. I will also tell the reason for saying so. According to the Report of the Parliamentary Standing Committee Tabled in this August House in the month of March 2017, it has been categorically stated that there are 4,00,294 elementary school teachers in Government schools which are still untrained. This is the observation of the Committee. This accounts for 9.24 per cent of the total number of Government school teachers. Further, why the Minister's statement could be wrong can be substantiated by another factor. According to the Education Statistics- At a Glance Report by his own Ministry, the total number of diploma-level training institutes in the country are about 4,730. With these 4,730 teachers' training institutes, it is impossible, from April to July, to train the teachers. Even if the Minister's statement is believed to be correct, it is impossible for the Government to impart the training to three lakh teachers from April to July.

Sir, the second concern which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is regarding acute shortage of teachers. Sir, the Standing Committee on Human Resources Development — I have not invented the figures; it is the Report of the Standing Committee from which I have taken figures and I am reiterating them here — in 2017 noted that around 9 lakh vacancies of teachers exist at elementary level across the country out of the total sanctioned posts of 52 lakh teachers. Hence, approximately 17 per cent of total sanctioned posts are lying vacant. This is the position so far as vacancies are concerned. About 1,05,000 schools in the country are single-teacher schools. Even though there are classes from 1 to 5, and from 6 to 10, there are so many elementary schools in this country which are run by single teacher. Therefore, I request the hon. Minister to fill the vacancies immediately and address the problem.

The third concern which I would like to bring to the notice of the hon. Minister, through you, is that there are a large number of teachers, both in public and private schools, on contractual basis. It is not only at the primary school level, but also at the secondary school level and also at the professional institutes. There are so many institutes where the Government of India is engaging professors and teachers on contractual basis which is against the spirit of law. There are about 6,66,000 teachers in Government schools and

3,66,000 teachers in private schools who are engaged on contractual basis. First of all, they are low-paid; they are under-qualified. Sir, the fourth point, which I would like to make, is that the majority of the teachers in the country are all burdened not only with the teaching activity but non-teaching duties also. Many Government school teachers are sent for Housing Survey, Economic Survey, Industrial Survey, Census duty, Voter Identity Card duty, etc. There are so many job responsibilities which are entrusted to the teachers, which is not in accordance with the hon. Supreme Court judgment. Therefore, I urge upon the Government to stop this practice of engaging the teachers for non-teaching duties.

Now, Sir, I will conclude as directed by you. The last point, which I would like to bring to the notice of the Government, is that the Right to Education Act had promised primary education for 470 million children in our country. According to the Census of 2011, 4.3 million children in India are still child labours, thus excluded from education and school.

So, with these five points, I conclude my observations and request the hon. Minister to address all the five issues so that the education system, in India, is made perfect. Thank you, Sir.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, while I rise to support this Bill, I would like to underline the fact that the Bill is an admission of our failure. When I say this, it is a collective failure. It is a failure of the Central Government. It is a failure of the State Governments. It is a failure of all of us. It is a collective failure because we, the Parliament, enacted the legislation in 2009 and we could not succeed in meeting the provisions of the Act within the stipulated time. Now, we are asking for some more extension, that is, for four years. It is an admission. I am cynical on this issue whether within four years we will be able to achieve that. Again, I am giving a warning because the Bill is seeking a four-year extension. Will we be able to succeed? If we have the will power, we can do it within two years also.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the two-year period is retrospective.

SHRI D. RAJA: The Bill seeks extension for four years. The Cabinet acceded five years. Now, it is up to 2019, that is, two years from now. Two years have already passed. I am doubtful whether we will be able to achieve it within two years. If the Minister is confident, he should show us as to what roadmap the Government will achieve this. I am telling all these things because 92 per cent of the teacher training institutes are run by the private sector. If my figure is wrong, I stand to be corrected. But 92 per cent of the

[Shri D. Raja]

teacher training institutions are run by the private sector. Then, 10 per cent of our schools are single-teacher schools even today. The States are recruiting low-paid, unqualified teachers. It is a violation of the RTE Act. So, what will the Government do? The Central Government will have to spend more. You are talking about the Financial Memorandum. But that is not enough. The Centre will have to spend more on education. The States will have to spend more on education. Education is the strength of the nation. It is the strength of the society in which we live, and education is power. I can quote Thiruvalluvar, the great philosopher and guide. He said, "Education is the wealth" — and it has been translated by many authors, including Kanimozhi's father, the former Chief Minister of Tamil Nadu — "which cannot be destroyed, and no wealth can be equated with education as wealth." That is what Thiruvalluvar has said. So, we should understand the power of education. Education empowers the people. Education helps people to overcome the difficulties and ordeals.

Sir, having said that, I would like to say that when the RTE Act was passed by the Parliament, I did point out several things. Now, this Act takes care of children in the age group of 6 to 14 years. But, what happens to the children in the age group of 0 to 6 years? What happens to the children in the age group of 14 to 18 years? The Act doesn't speak about it. In fact, in several countries, even in many Western countries, till the secondary education, it is in the Government sector. And, in fact, in many countries, it is free and compulsory in true sense but, here, we do not have that system. Even now the Government can think of providing free and compulsory education up to secondary level; in some places, even up to graduation for SC/ST, some State Governments have announced free education but we should think of providing free and compulsory education to our children up to secondary level, and here, you can prohibit child labour totally, and, it is possible also. Now, 25 per cent seats are given to weaker sections of the society. How many private schools are really implementing this? If they are implementing it, do they allow the SC, ST or OBC students to get into their schools? Please make a study. I am not asking you to reply right now. But there are problems. This 25 per cent reservation to weaker sections does not help the SC, ST or OBC students to get admission.

Sir, teachers' training is an important aspect and modern techniques need to be practiced to train the teachers. The elementary teachers play a remarkable role in shaping the character of the children, the personality of the children. Even today, if you ask me, I can write volumes about my elementary school teacher who taught me simple arithmetic

and ABC. What I am saying is that this thought should be taken into serious consideration. ...*(Time-bell rings)*... I am concluding, Sir.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, he is not talking about Katchatheevu, give him more time.

SHRI D. RAJA: Sir, the Act speaks about the minimum working days. For 245 days, the children will have to go to school and remain in school from 8.00 a.m. to 4.00 p.m. Sir, let me tell you, personally, several children called me. In Delhi here, several children called me after I told them that the Parliament is going to take up this issue. They said that Saturday is working day. Sir, Saturday and Sunday should be holiday for children.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is very correct. I agree with you.

SHRI D. RAJA: The Central Government employees work only for five days but you are saying that children have to go to school on Saturday also. Sir, the working parents find it very difficult to spend time with children. Let us understand our children, their psychology. Home work is also an issue. Many burdens are there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are correct. ...*(Time-bell rings)*...

SHRI D. RAJA: Sir, regarding Mid-day Meal Scheme, we will have to create conditions for our children to go to school and learn adequately. Mid-day Meal workers and Anganwadi workers are treated as scheme workers. Treat them as regular workers, give them all protection, which other regular workers get so that they provide good conditions for our children. ...*(Time-bell rings)*...

Sir, it is time that we, as a civilized society, should take responsibility to provide good material conditions, suitable academic conditions for our children. We have to do it for our children. They are the future of our nation. So, we should take up the responsibility. The Government should show some political will that we will do everything possible for the children and ensure quality education for our children. Sir, the concept of free and compulsory education should not remain only in paper or words, it should be actually practised. That is my plea. With these words, I support the Bill. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity to participate in this debate. Sir, before I start, while following the ethics, I would like to disclose that I am associated with a private school.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please proceed.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, the RTE Act is in operation for the last seven years. It is one of the landmark legislations which the Parliament has passed in the recent years. After amending the Constitution and Article 21A, this legislation was essential and the Parliament unanimously passed this legislation. It is time for us to review its implementation. Seven years is quite a considerable time to review any programme or plan and this is the right time, though only one clause of the Bill is amended to extend the training period from 31st March, 2015 to 31st March, 2020. There itself, it is one of the failures. To overcome the failure, we are bringing forward this amendment.

Sir, this Act has done a lot of good. Several achievements are there. To say that there are no achievements is not correct. The important thing in this amendment of making education a Fundamental Right is that the burden of educating a child in the age group of 6-14 years has been shifted primarily from parents to the State. Today it is the responsibility of the State to provide free, compulsory and quality education to a child and no child should be left out. Not a single child should be left out. State is responsible and accountable. What does it want to achieve? It is both the Central Government and the State Governments that have been entrusted with the responsibility. Both are partners. Education is in Concurrent List. It is the responsibility of the Centre; it is the responsibility of the States. So, nobody can escape the responsibility. Now, the Act has been in operation for seven years. Let us see how far we have succeeded, how far we have failed and how we can overcome the failure.

Sir, there are several responsibilities imposed on the State Governments and the Central Government under the Act. The first and major responsibility is survey of neighbourhood. It is only through survey of neighbourhood children that the State will come to know as to how many children are available there who are to be educated, who are from deprived section of the society, like Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs. This is through the Panchayats. That is the obligation under the Act. Sir, the hon. Minister can apprise the House about it. Seventy per cent of the survey has not taken place. If seventy per cent of the survey has not taken place, then how do you implement this Act? Pardon me for saying this. Today this Act is implemented not with love and affection by taking cooperation of everybody, it is implemented through the power of the State, which you cannot succeed. I remember, Sir, while this Bill was being debated in this House, I had said that. Then it was the UPA Government. I had cautioned the HRD Minister. As my colleague Mr. Shri Derek O'Brien said, there are five partners in this. ...*(Interruptions)*...

There are five stakeholders also while educating these children. What is the responsibility in the Act which you have done? Where is the cooperation of all these people? There is nothing. Except a school management committee, the parents are not involved in finding out or in assessing what this thing is. The schools are not involved, the management is not involved. Who is involved is the block education officer of the State Government. I had spoken four years back when the Bill was debated. Today, I have no hesitation in repeating that it is full of corruption at the block education officer level as far as I can tell you of my State. It is because today there is a 25 per cent reservation in private schools for deprived sections of society. If you take a survey today, it is by money power because the private schools' fee is very high. A racket is there through the block education officer to get the seats in the private schools, online, whereas the responsibility given is to make a survey and assess the deprived sections in the neighbourhood locality. Then, the Act has given about finding the neighbourhood. Every year they will change the neighbourhood. One day it is one kilometres, another day it is four kilometres. Third day, they say it is ten kilomtres and after that in the entire area there is no neighbourhood; the entire city is a neighbourhood! This will not achieve the purpose. Private schools play a very important role in our system. Some may not be good because there are black sheep in every system. They are providing you lakhs and lakhs of free seats. Where are they involved? Where is their suggestion taken? Who will study their problems? There is a conflict between the CBSE and the State. CBSE schools issue one circular and the State Government issues another circular. You do not like to take into consideration the problems of private schools when you take so much of seats from them for free. You have not found out whether the State Governments have reimbursed their fee or not. It is not known. Yes, it is a social obligation. Private schools have to take this responsibility, but discuss with them. Find out how much more effectively they can implement the provisions of Right to Compulsory Education. There is absolutely no say for the private schools in the entire implementation of the RTE Act whereas they are the biggest contributors for you.

Then, comes the fee structure. It is a common sense that you are taking away 25 per cent of the seats of the private institutions. Yes, it is an obligation. But, at the same time, their problems may also be taken into consideration when they are contributing 25 per cent of their seats. How are they compensated? How are their problems looked into? There is no Committee of the private schools and the Government. The State Government is not consulting them. The State Government is looking to this private management who are giving 25 per cent of the seats, which is several lakhs, and about which the hon. Minister knows the correct figure. They are looked upon as thieves by the State Governments, by the bureaucracy.

[Shri K. Rahman Khan]

5.00 P.M.

So, you have left everything at the mercy of the bureaucracy and whatever they decide is decided; there is no involvement of anybody. I request the hon. Minister that the CBSE has a great role to play. But there should be some consistency. The CBSE should have consultation with the private schools because they have the largest number of schools in the country. How can the CBSE just say that they have no responsibility; they just issue circular and keep quiet?

Then, come to the financial aspect. What we have now, at present, are the best reviews by the CAG Report. Now, the CAG Report has just been laid on the Table of the Parliament. Now, what does it say? I am just mentioning the conclusion. The CAG Report says, in its conclusion, "There is no separate budget for RTE and it is subsumed in *Sarva Shiksha Abhiyan* Budget." How can it be? How will you achieve the RTE objective when you just make it a part of a big *Sarva Shiksha Abhiyan?* It further says, "The AWP&B was not used as an input for the budgeting exercise in Government of India and States. The unspent balances at the end of the year did not match with the opening balance of the succeeding years for all the years during 2010 to 2016 as per the Utilization Certificates of MHRD. There were persistent closing balances and advances pending and there were cases of diversion/irregular release of funds, misappropriation of funds, and irregular utilization of grant, irregular depiction in annual accounts of SIS and delays in release of funds at various levels." This is the conclusion of the CAG Report as far as the utilization of funds is concerned. I mentioned about the survey. The CAG Report has also commented on this. "As per Rule 10 of the RTE Rules, the local authority shall maintain a record of all children in its jurisdiction, through a household survey, from their birth till they attain the age of 14 years. The record is to be updated annually and maintained in the public domain. Audit noted that regular household surveys were conducted to record and update the information of all children up to the age of 14 years in 14 States/UTs; while no such regular surveys were conducted in the remaining 21 States/ UTs. Since, the household survey was not carried out, vital information *viz.,* number of children in the age group of zero to 14 years,-number of children attending schools, out of School Children etc., have not been captured and updated annually." Sir, then there is poor retention rate in Government schools. Have we discussed about this problem? After the RTE is introduced, the private schools were giving 25 per cent of seats whereas the Government schools are closing; there are no children and there is huge retention in

private schools as per the CAG Report. And, then, there is a huge drop-out in Government schools. The very purpose of this Act is to tackle the drop-out. It says about the analysis of UDISE data of drop-out percentage for a period of four years and it is in a tabular form. So, the highest drop-out is in Government schools.

Then, the next point is regarding conditions of Government schools. Every Government school should have certain infrastructure under the Act. It is mandated. Nobody has surveyed whether all the Government schools have got the minimum infrastructure. It talks about the minimum infrastructure. There is no minimum infrastructure in most of the schools. Only 50 per cent of the schools have got electricity and 50 per cent of the schools have no electricity. Out of 10,75,000 Government managed schools, only 6,00,023 schools have got electricity and there are 4,00,000 schools which have no electricity. What I am telling you, Sir, is that all these things are mentioned in the Act, by the implementation of the Act. Provision of minimum infrastructure, physical infrastructure and teachers is the responsibility of the Government in Government schools. If you don't provide infrastructure in the Government schools, how do you expect the children to go to the Government schools? You are depriving the parents. All private schools cannot take them. You are doing discrimination. Only a few people can go to the private schools who are either influential or get admission under the 25 per cent quota. But what about the 75 per cent of the children? Where do they go? What type of quality education are you giving? So, my suggestion to the hon. Minister is, let there be public involvement, stakeholders' involvement and private schools' involvement. It is the duty of private schools and public schools. It is the duty of all of us. This is the time for taking stock of the RTE Act. This is one of the landmark legislations. Let us really make our people feel that this is the legislation which changed the destiny of the nation. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva, even though you are not the next speaker, I have to break the order because I want you to come here after your speech. So, now I am allowing you. But your time is five minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Bill, on behalf of my party DMK, which seeks to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, to extend the deadline for the teachers to acquire the prescribed minimum qualification. Sir, a true democracy is one where education is universal. And based on that, the 2009 RTE Act was enacted. Sir, the quality of a nation depends upon the quality of its citizens. The quality of the citizens, though not exclusively, but on crucial

[Shri Tiruchi Siva]

factors, depends upon the quality of education. And the quality of education, undoubtedly, depends upon the quality of teachers. So, is it suffice to prescribe minimum qualification for the teachers alone? That is the question. What is the standard or quality of education which is imparted to our students today? Sir, the recent report says that 60 per cent of the engineering graduates are unemployed. More alarming report has come from ISRO that only 26 per cent of the passed out engineering graduates are employable. And that is where it starts from. It starts from the primary level, upper primary level and reaches up to the higher education level. Sir, we say that we have got too many educational institutions, the universities have multiplied, there are more number of colleges, but as far as the quality of education is concerned, as pointed out by Shri K. Rahman Khan, we do not compare ourselves with the neighbours. The number of educational institutions does not signify or qualify education's quality. So it implies that the Government has got more responsibility to improve the quality of education. Sir, I would like to point out some reports here and I think the Minister would take it into consideration; rather, he might have been already aware of it. India's educational card shows ample room for improvement. The World Economic Forum's Human Capital Index which takes into account the educational quality in addition to access ranked India at 78 out of 122 countries. The latest United Nations Human Development Report put India's mean years of schooling at just over 4, and its literacy rate for those 15 and above, at a low of 63 per cent. Sir, further as per the Annual Status of Education Report Survey, 2014, which is administered by the Indian NGO Pratham, it was found that learning of Mathematics is a serious and major source of concern. As per the All India (Rural) figures for basic arithmetic in 2014, only 25.3 per cent of Class 3 students could do a basic two-digit subtraction. For Class 5 students, the proportion of students who could do a basic two-digit subtraction was just minutely higher at 26.1 per cent. Sir, up to Class 3 they are not able to do two digit subtraction, and up to class 5 they can do only two digit subtraction. What is even more worrying is that the percentage of Class 2 students who cannot recognize numbers up to 9 increased over time, from 11.3 per cent in 2012 to 19.5 per cent in 2014. These are not just statistics. The Government has to concentrate more on that, and find out what are the reasons for that.

As my colleague, Mr. Vijayasai Reddy has pointed out there are nine lakh teachers' vacancies in the country. The teacher and students ratio is disproportionate. In Uttar Pradesh itself the vacancy position is 1.75 lakh. In the whole of the country, the vacancy position is nine lakhs. There are so many vacancies lying. Those teachers who are already employed are still lacking the minimum qualification means, we call ourselves

as a developing country and soon we are going to call ourselves as a developed country! But the quality of education at this level is only because of the non filling of teachers' vacancies. What are the steps the Government is taking to fill up the vacancies? As Mr. Derek O'Brien has pointed out, it should come to the States again as it was before the Emergency. Education must come to the States. Now that is in the Concurrent List, we are not able to do anything on our own because sometimes we are dictated by the Centre.

Sir, the Ministry of Human Resource Development has commissioned two studies for the attendance assessment rate of students and teachers in 2006-07 and 2012-13, within a period of five years. As per the study, 15.2 per cent of the teachers at primary schools were absent during 2012-13. The figure was worse for the upper primary schools, with teacher absenteeism at 16.9 per cent during 2012-13. ...*(Time-bell rings)*...

I will take one minute. I would like to quote a judgement given by the Rajasthan High Court in May, 2015 in the Syed Sahid Ali *Vs.* Director, Secondary Education and others, the court ordered that assigning additional non-teaching responsibilities to teachers needs to be seriously considered. The Board results of the school in question in the case showed a sharp decline in its performance, with the result of the students in the Class 10 Mathematics examination declining from 77.41 per cent to 20.73 per cent .... in 2012-13. Earlier, I had moved a Private Members Bill also that assigning non-academic duties to the teachers deprives the quality of education in our country. Already we are facing a shortage of teachers in schools. The teacher and student ratio is not proportionate; and assigning them other duties like elections, surveying and other things much more minimize the quality of education. So, as you said, the Bill may be extended for four years. But the left out years are only two because the Bill has been brought up for discussion very late. Only within two years he can fill up the vacant posts with minimum qualifications. But we do need adequate number of teachers to fill up all the vacancies. So also the quality of education has to be improved. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Viplove Thakur.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया।

श्री उपसभापतिः आपके पास इस पर बोलने के लिए सिर्फ पांच मिनट हैं।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः जी हां। वह तो मैं समझ गई हूं।

उपसभापति महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और डा. मनमोहन सिंह जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यू.पी.ए. सरकार के समय में "राइट टू एजुकेशन", राइट टू इन्फॉर्मेशन", "राइट टू फूड

[श्रीमती विप्लव ठाकुर]

सिक्योरिटी" और "मनरेगा" जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किए थे। इनका उस समय बहुत ज्यादा विरोध किया गया था, लेकिन आज इन्हीं कार्यक्रमों को सबसे ज्यादा माना जा रहा है, इसलिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

महोदय, आज जो बिल माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर जी लाए हैं, इसमें उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग की बात कही है और Right to Education for the children की बात की है। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूँ कि इनको सबसे पहले norms बदलने चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल है, जिसे elementary कहा जा रहा है, वहाँ पर बच्चों की strength के ऊपर टीचर्स रखे जाते हैं। वे इस बात को देखते हुए नहीं रखे जाते कि बच्चा आया है, उसे क, ख, ग भी सीखना है, 1, 2, 3 भी सीखना है, उसको attention चाहिए, उसको इतना personal attention चाहिए, जिससे कि उसको बताया जा सके कि आपको इस तरह से लिखना है। आजकल writing के ऊपर

[उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा) *पीठासीन हुए]*

तो किसी तरह का दबाव ही नहीं है। आप आज के बच्चों की writing देख लीजिए। आप भी नहीं पढ़ सकेंगे, टीचर्स नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले primary schools में बच्चों के लिए, पहली क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, दूसरी क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, यानी पाँच क्लासेज़ के लिए पाँच टीचर्स होने चाहिए, तभी हम उनका बेस बना सकते हैं, नहीं तो उनका बेस नहीं बन सकता है।

आज सबसे बड़ी बात शहरों की और गाँवों की आ रही है। शहरों और गाँवों के बीच का जो फर्क़ आ रहा है, वह इसी वजह से आ रहा है। आज हम पढ़ते हैं कि एक रिक्शा वाले की बच्ची ने भी IAS पास कर लिया, वह भी competition में आ गयी, क्योंकि वह शहर में पढ़ती है। गाँव के कितने बच्चे competition में आये हैं? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है, वह बहुत ही नीचा है। इसलिए, पहले तो यह सोचना है कि उन पाँचों क्लासेज़ के लिए पाँच अध्यापक रखे जाएँ। उसके ऊपर strength की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर एक क्लास में या एक स्कूल में 20 बच्चे हैं, तो वहाँ दो टीचर्स दिये जायेंगे या वहाँ तीन टीचर्स दिये जायेंगे, नहीं! अगर हम अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को सही रूप में शिक्षा देना चाहते हैं, तो पाँचवीं क्लास तक पाँच टीचर्स होने चाहिए, जिससे कि उन बच्चों का foundation बन सके और वे आगे के लिए योग्य हो सकें। आपने यह कहा है और आज हमें देखना है, हमें सोचना है कि हमरी शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है। हम बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, कॉलेजेज़ की बात कर रहे हैं, IITs की बात कर रहे हैं, IIMs की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेज़ खोलने जा रहे हैं, लेकिन उनमें कौन से बच्चे आ रहे हैं, हमारे गाँवों से कितने बच्चे वहाँ जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। उसमें जो कसूर है, वह शिक्षा विभाग का है, शिक्षा प्रणाली का है, शिक्षा पद्धति का है, जिसे हमें सुधार में लाना है।

आपने प्राइवेट स्कूल की बात की है या औरों की बात की है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप पहले यह तो सर्वे करवायें कि कस्बों में जो प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, गाँवों में जो प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, उनका क्या ढाँचा है, उनको किस बात के ऊपर लाइसेंस दिया जाता है, किस बात के

ऊपर परमिशन दी जाती है। दो-दो कमरों में वे स्कूल्स खुल रहे हैं। क्या वे बच्चों को शिक्षा दे पायेंगे, क्या वे बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पायेंगे? लेकिन, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म है, वहाँ English medium है, तो गाँव का भी जो बच्चा है, उसके पैरेंट्स उसको उस स्कूल में भेजना चाहेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहेंगे।

सर, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन तब हम अंग्रेज़ी के इतने अधीन नहीं थे, जितने आज हो गये हैं। आज अंग्रेज़ी भाषा हमारे ऊपर हावी हो गयी है। आज अंग्रेज़ी भाषा के लिए हमें हर बात करनी पड़ रही है। इसलिए मैं यह चाहूँगी किं अग्रेज़ी हमारे प्राइमरी स्कूल्स से भी शुरू होनी चाहिए, जिससे कि गाँव का बच्चा भी उसका फायदा उठा सके। इसके लिए हमें टीचर्स देने होंगे। आज हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा इस competition में आये, वह अंग्रेज़ी बोल सके। आज यहाँ का जो modern concept हो गया है, वह यही हो गया है कि जो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है, जो अंग्रेज़ी में अच्छी तरह से बातचीत कर सकता है, वह पढ़ा-लिखा है, चाहे उसने डिग्री ली है या नहीं ली है। इसलिए मंत्री जी, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा।

आपने ट्रेनिंग की बात की है, लेकिन उन टीचर्स के लिए क्या करेंगे, जो already trained हैं और पढ़ा रहे हैं, ...(समय की घंटी)... जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है? मैंने अभी एक डॉक्युमेंटरी देखी। जब यूपी में टीचर्स से पूछा जाता है कि हमारे प्रधान मंत्री कौन हैं, तो उनको पता नहीं है। यहां के मुख्य मंत्री कौन हैं, इसके बारे में उनको नहीं पता है। आप अनट्रेंड टीचर्स को तो ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कोई reorientation camp उनके लिए भी लगाने जा रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। आज वे पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे हैं, जब कि नई-नई चीजें आ रही हैं, modern concepts आ रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें आ रही हैं, जिनके बारे में उनको पता नहीं है, इसलिए इनके साथ-साथ उनको भी ट्रेनिंग देने की बात कीजिए, मशरूम की तरह स्कूल खोलने की बात मत कीजिए। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं खत्म करने जा रही हूँ। आज प्राइवेट स्कूल हर गाँव, कस्बे में मशरूम की तरह खुल रहे हैं। आप उनका स्टेंडर्ड देखिए। जब स्कूल खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, तब आप इस बात को देखिए। ...(**समय की घंटी**)... आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सर्विस उसमें जोड़ी जाएगी? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जो यह बिल लाए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से लागू कीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द!

DR. PRABHAKAR KORE (Karnataka): Thank you, Vice-Chairman, Sir.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): आपको जन्म दिन की बधाई।

DR. PRABHAKAR KORE: Thank you. Sir, it is my personal interest. I am a Chairman of the one of the education institutions where we are running these schools. There is no personal interest, Sir, for these. Sir, this Act was passed seven years back. For the past seven years, they could not train a teacher. This is my first question. Even if they are given extensions also whether it is possible that they can train the existing teachers. If you have not trained them, you are going to bring the same Bill. So, please make it compulsory for the non-eligibility teachers that they must complete their

[Dr. Prabhakar Kore]

minimum qualification within the next three or four years. Sir, when this Act has come, my colleague has spoken about private schools and private colleges in this country. Sir, particularly in Karnataka, 60 per cent schools are run by the private people like philanthropists, missionaries, etc. Their contribution to education in this country is tremendous. Once Mr. Narayana Murthy said in Karnataka that IT in Bangalore is not because of a good city or good weather or good citizens, the IT has come in Bangalore because of good quality of HRD. That is more important. This HRD is done by the private colleges. Coming to the Government-run schools, Sir, we have come from a small place. We studied in Government schools in those days. But today there is no qualified teacher. There are no teachers, in fact, who are interested in teaching. They come for job, for the sake of salary, spend their time and just go. There is no accountability for teachers. We have failed in Government schools because there is no accountability whether they are teaching or not. I will give you one example, Sir. I have a High School in Solapur in Maharashtra from where you come. It is almost eighty years old High School. The result of the school for the last ten years, three years back, had come down to 30 per cent. Then I called the teachers to know what is the problem and why results are going down. It is a private institution. Of course, the teachers are grant-in-aid teachers. I asked them why poor result has come. सर, इस स्कूल में जो बच्चे आते हैं, वे गरीब बच्चे हैं और वे गांव से आते हैं। This is the fixed reply. Then three years back, I told them that I am going to close this school because whatever students are coming, you are telling that, वे क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं हैं, सब गरीब बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं, तो हम इस स्कूल को बंद कर रहे हैं और आप लोग दूसरी नौकरी देखिए। हमने इस तरह का नोटिस भी दिया। I told that on next first, I am closing this school. You believe it or not that for the last three years after giving this notice -- they were given one more opportunity -- the result is 100 per with same teachers and same students. So, why not take action against the Government school teachers? There is no accountability. जो बच्चे अभी स्कूलों में आ रहे हैं, my colleague has spoken about this Bill. जो बच्चे select होते हैं, I think, if you study, most of the students come from these private schools under the RTE Act. Their minimum income is much more than what they show. उन्हें तहसीलदार से certificate मिल जाता है कि इस परिवार की income कम है। उसके आधार पर वे आ जाते हैं। कम से कम परिवार की income तो देखी जानी चाहिए। There are many examples. इस तरह वे आते हैं तो Government उनकी फीस देगी, otherwise प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं देती है। This is the position. As per my personal experience, of under this RTE Act, जितने बच्चे आते हैं, उनमें 50 परसेंट fake होते हैं। I think you have to make some mechanism. Sir, there is one more

problem regarding this small issue. जब भी Government change होती है, I want to bring to the notice of the HRD Minister that I appreciate him. Every Minister wants to introduce something new. जो भी नया मंत्री आता है, नई policy लेकर आता है। Last Government में कहा गया कि हम counselling totally abolish करेंगे, जैसे AICT है, UGC है, Medical Council है, Dental Council है, सबमें abolish करके हम Knowledge Commission बनाएंगे। यह क्या हो रहा है? आज हमारे देश में एक नवीन system NEET का शुरू हो गया है। Sir, I am very sorry to talk about NEET. आप देखें कि आज 10+ exam कौन लेते हैं - State Government सब जगह लेती है। तमिलनाडु में State Government लेती है। कर्णाटक में State Government लेती है। Today, Sir, the first list has come out from NEET. There was not a single boy from Karnataka who has been selected in a medical college. How are we balancing this education system? Forget about rural areas.

श्री जयराम रमेशः आपकी सरकार ने यह किया है। ...(व्यवधान)...

डा. प्रभाकर कोरेः वह हमारी सरकार ने नहीं किया, hon. सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अभी next 5 years में आप देखें कि जो बच्चे NEET की Post Graduation seats के लिए select हुए हैं, there are many colleges where you will find that there is no seat taken. आज, Medical में Post Graduation की काफी सीटें खाली हैं। Engineering Colleges का हाल तो बहुत बुरा है। More than 50 per cent seats are vacant in engineering colleges because there is no quality, there is no employment. So, you have to review this whole system, not just primary. Primary is most important because it is the foundation. Sir, I was reading one book. उसमें लिखा है कि Second World War के समय Churchill के सामने यह प्रकरण आया कि England में उनके सभी financial resources खत्म हो गए हैं। वहां के Finance Minister ने आकर कहा कि 'Out budget is totally over. I think we have money only in HRD Department'. उस समय Churchill ने Minister को बुलाकर कहा कि - 'We can build new England, but not a new HRD for UK'. That was what Churchill said. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में HRD या शिक्षा की कितनी importance है।

For the last 35 years I have been involved in the education sytesm. The most neglected Department is the most important Department in this country. Sometimes we feel sorry that जिधर Government touch होता है, वहां सब बरबाद हो जाता है, ऐसी धारणा-सी बन गई है। पहले यहां सब free था, if people want to open a school, let them open. The market will decide which school will run, which school will not run. This is happening for engineering colleges. Still, students are going to good and quality engineering colleges. Still, the demand is there. आज हमारे देश में हालत ऐसी हो गई है कि not even one single university is within the top 100 in the world, including IIT ...*(Interruptions)*... for example, Malaysia. Sir, there are two universities in a small country whose ranking is

[डा. प्रभाकर कोरे]

within 50. In fact, we teach Malaysia how to start an educational institution. The entire education system in Malaysia is following the Indian system. I support this Bill. But, my only request to hon. Minister is not to come before the House again for extension. That is my request. You are giving time; three years is more than sufficient. As my colleagues know, when this Act passed, new schools came up like mushrooms. When you have said that it is not compulsory, all schools are closed now. आपके पास बी.एड की क्वॉलिफिकेशन प्राप्त करने के लिए भी स्कूल्स नहीं हैं। This is the position. आप इस पर भी चिंतन कीजिए, So, unless and until you give good training and accountability, it is not easy to improve the situation. At least, assessment of teachers should be made annually. You should make teachers to attend conferences, etc. यही मेर सजेशन है।

With these words, I support the Bill. Thank you.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

महोदय, यह विधेयक अनट्रेंड टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए है। जब माननीय मंत्री जी इसे सदन के पटल पर रख रहे थे, तो इन्होंने यह जानकारी दी कि प्राथमिक स्तर पर कुल 67.41 लाख शिक्षकों में से 11 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, जिनमें से 5.12 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के हैं और 5.9 लाख निजी स्कूलों के हैं। जो टीचर्स अप्रशिक्षित हैं, इस विधेयक के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसमें उसकी अवधि का विस्तार हो रहा है, इसके लिए मैं इसका समर्थन करती हूँ।

माननीय मंत्री जी इस विधेयक के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे बच्चों और शहरी इलाकों में CBSE और ICSE स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के बीच के फर्क़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वह फर्क़ दूर होगा? आज भी बहुत से ऐसे गार्जियंस हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निजी स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सरकारी स्कूलों पर कम ध्यान देते हैं। निजी स्कूलों का मन इतना बढ़ गया है कि अगर लोग वहाँ ऐडमिशन कराने जाएँ, तो वे आम लोगों के बच्चों का ऐडमिशन नहीं लेते, लेकिन लोग वहाँ ऐडमिशन लेने के लिए परेशान रहते हैं। शिक्षा के स्तर में कहीं न कहीं कमी आई है। मंत्री महोदय, सरकारी शिक्षा दी जा रही है, उसका विस्तार भी हो रहा है और उस पर पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी में सुधार कैसे आएगा, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ देख रहे हैं, जो गार्जियंस यह चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएँ, वे सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं यह इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है। मेरे माँ-बाप की भी यह इच्छा थी कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में जाऊँ, लेकिन कई तरह की परेशानियाँ थीं, जिनके कारण मैं उस स्कूल में नहीं जा पाई।

सर, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि अगर हम बिहार की बात करें, तो माननीय मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली, तो उन्होंने सबसे पहला ध्यान तालीम की तरफ दिया, क्योंकि तालीम ही तरक्की की कुँजी होती है। जब गाँवों की लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, जब उन्होंने पाँचवीं और छठी कक्षा के बाद पढ़ना छोड़ दिया था, तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने "साईकिल योजना" की शुरुआत की। पहले जब गाँवों और छोटे शहरों में लड़कियाँ साईकिल चलाती थीं, तो उन पर लोग फब्तियाँ कसते थे और उनके माता-पिता को उल्टी-सीधी बातें कहते थें, लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने "साईकिल योजना" की शुरुआत की, तो उसका जबर्दस्त असर यह हुआ कि लड़कियाँ पढ़ने के लिए आगे बढ़ीं, उनको देखकर लड़के भी आगे पढ़ने लगे और हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल के बाहर थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे स्कूल आकर पढ़ने लगे। एक आंकड़ा हमारे पास है। यह नेशनल सैम्पल सर्वे का डाटा है। पूरे हिन्दुस्तान में हिन्दू समुदाय के रूरल इलाके के 3 परसेंट बच्चे स्कूल से बाहर हैं और मुस्लिम समुदाय के रूरल इलाके के 4.3 परसेंट बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अर्बन में हिन्दू 2 परसेंट बाहर हैं और मुस्लिम में 4.6 परसेंट बच्चे बाहर हैं। दूसरा नेशनल सर्वे जो बता रहा है, वह यह है कि 6 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वे स्कूलों में 26.7 लाख हैं, जिसमें मेल की तादाद 18 लाख है और फीमेल की तादाद 15.9 लाख है। यह इस बात की गवाही दे रहा है कि लड़कियों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जागी है, ज्यादा लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़के स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह बात कही गई है कि जिस मआशरे में तालीम नहीं, जिस मआशरे में तिजारत नहीं वह अमाशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम किसी भी चीज़ की बुलन्दी की बात करते हैं, हम एक अच्छी इमारत की बात करते हैं तो उसके लिए एक अच्छी नींव की जरूरत है। अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से होगी, उनकी नींव मजबूत रखी जाएगी तो इमारत की तरह ही वे बच्चे शानदार और जानदार बनेंगे।

माननीय मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि सरकारी स्कूल पर तो ध्यान दें ही, साथ ही निजी स्कूलों की जो मनमानी हो रही है, इस पर लगाम लगने के लिए आप जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन करें। उसमें सांसदों और विधायकों को सदस्य जरूर बनाएं। दूसरी बात, मैं आपसे यह कहना चाह रही हूं कि जो 40 बच्चों में एक टीचर है और अभी बताया गया कि पूरे हिन्दुस्तान में टीचर्स की 9 लाख वेकेंसीज़ है। 10 परसेंट ऐसे स्कूल हैं जहां सिंगल टीचर है। इन वेकेंसीज़ का भरने की आवश्यकता है। आपने अपने सम्बोधन में बताया कि जो स्वयंप्रभा योजना है, उसमें 32 चैनल हैं, ये तीन बार दिखाए जाएंगे। इससे जो अप्रशिक्षित, अनट्रेंड टीचर्स हैं वे ट्रेंड होंगे। लेकिन आपको यह भी बताना होगा कि ट्रेंड टीचर्स का किस तरह से हम एग्जाम लेंगे? पहले जो 55 लाख टीचर्स ट्रेंड हो चुके हैं, तो क्या इनको भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? मैं यह इसलिए कह रही हूं कि बहुत सारे गार्जियंस जो निजी स्कूलों की तरफ ध्यान देते हैं, वे इसलिए देते हैं कि वहां के टीचर्स स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, ताकि उनके बच्चे भी स्मार्ट बन सकें। हमारे टीचर्स जब स्मार्ट होंगे तब हमारे बच्चे भी स्मार्ट होंगे। हमारे बच्चे जब स्मार्ट होंगे तो वे, जो निजी स्कूल के बच्चे हैं, उनको यह कहने पर मजबूर होंगे, जो मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूंः

"घर से है क्या मतलब, स्कूल हो वतन मेरा,
मर जाएंगे किताबों में, वर्क होगा कफन मेरा।"

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise in support of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017. A lot has been said about education by my senior colleagues. In this Amendment Bill, a very specific thing has been added that hitherto those teachers who are there in the position and have not acquired the required minimum qualification till 31st of March, 2015, will have to complete it in four years of time, that is, by 2019. This has been stated by the hon. Minister also. I congratulate the HRD Minister, Shri Javadekarji, for introducing this important piece of legislation.

Sir, I have to seek some clarifications from the hon. Minister. I won't repeat what has already been said. Education has been a very integral part of the economy and it helps in developing knowledge and all that. This has already been said. What I want to know from the hon. Minister is this. Here in the legislation, it is mentioned, "shall acquire such minimum qualification within a period of four years from the date of commencement of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017." So, I would like to know from the hon. Minister from when will this amended Bill be enacted. Four years after 2017 means it will go up to 2021, or, four years after 31st March, 2015? Then, I think some terminology needs to be changed so that it gives you some idea as to when this enactment comes into being — whether it will be four years after the 2017 Amended Act has come or..... So, that explanation needs to be given.

Another important point for which I want an explanation from the hon. HRD Minister is this. The number of teachers that would be trained is like this. There are about 7,00,000 teachers in the private schools and about 4,00,000 teachers in the Government schools. So, a total of 11,00,000 teachers would be trained and they will be having compulsory education, which needs to be completed in four years of time. Sir, there are institutions which will be imparting Diploma or B.Ed Degree. Will that be sufficient time for them? What will be the fate of those who are left out? Now we are in 2017. There are teachers who did not complete their compulsory education by 31st March, 2015 and there are some who got themselves enrolled after that. What will be the fate of those who are left out and who are not able to complete or acquire the education which is required of them by 2019? I think the Minister should enlighten the House about this. This is a very important piece of legislation, as far as elementary education is concerned. As of today, the plight of teachers is too bad in the State of Maharashtra and also at some other places, in the sense that they are taken up not on a regular basis and they are not made permanent in whichever institutions they go. They are taken up on contract. So, as it is, their mindset, their psyche is totally disturbed. This is what we have seen in Maharashtra.

Another thing that affects the plight of teachers is the dignity that ought to have been given to them. Today, teachers are looked down upon and they do not get the kind of dignity they should have got. Since times immemorial, what India has seen and what Hindustan has seen is that guru is held or revered in high esteem. As of today, we do the same thing. But, now, what has happened is that things have gone too low and everything is being counted, like what salary one draws, what standard of living the teacher is in, etc. According to that, in non-urban areas or even in urban areas, the standard of a teacher has really gone down. I think there has to be some improvement on that count. The main thing is that if you see the Government schools and the aided schools in non-urban areas, you will find that their infrastructure is completely of a low standard. It needs to be improved upon. Unless infrastructure is there, unless class-rooms are there, unless electricity is there and unless basic facilities which are needed to be accorded to the classrooms are there, the dropout rate will continue to go up and we will not be able to get the expected quality of teachers.

Sir, before I conclude, I will make my last point. In the State of Maharashtra, we start from elementary level; then, we go to secondary and then to higher level. What we have seen in the State of Maharashtra, particularly, in Mumbai University, is this. Today, the hon. Chief Minister of Maharashtra had to depose on the floor of the House regarding the plight of the students or what will happen to the students of Mumbai University where the results of the students are yet to be declared whereas it should have been declared in June. Sir, though education is a Concurrent subject, but I would urge the Central Government, the HRD Ministry, that proper budgeting should be done in every State. Some Members have said that if proper care is to be taken of children between the age group of 0-6, 6-14 and 14-18, then HRD, as an RTE, should have a proper budgeting. We are dwelling on some three and three-and-a-half per cent. It should go to six per cent. Then only will we be able to achieve the objectives which we have set in for education; and if education is rich, the country will be rich.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I have been waiting for an opportunity for a long time to participate in the discussion on an issue that has far-reaching implications on the capabilities of children seeking education both at primary and secondary level. In this backdrop, I welcome the initiative of the Government in moving this Amendment Bill for the consideration of this august House.

[Shrimati Wansuk Syiem]

We have made much headway with implementation of our flagship education programme *Sarva Shiksha Abhiyaan.* From the surveys conducted both by the Governmental agencies and NGOs on attaining declared targets set under *Sarva Shiksha Abhiyaan* programme, I find there is still lot to be done both on the development of infrastructure and improving the content and quality of teaching. The latest edition of the report regularly brought out by Pratham NGO — Annual Survey of Education Report — presents a mix of findings on key elements like reading ability, enrolment rates, drop-out rates and other incentives like mid-day meal scheme, etc.

The Amendment attempts to deploy *ad hoc* measures arising from the acute shortage of trained teachers by relaxing the minimum stipulated qualifications for a limited period of five years by which time it expects the teacher training infrastructure will be in place to address the manpower requirement projected under this Bill. From what is reported in the media, the state of teacher education in India is very dismal with the regulatory body National Council for Teacher Education abdicating its mandated responsibilities. It is interesting to note that the Council has served show cause notice to more than 3,800 teacher training institutes across India as to why their affiliation should not be withdrawn for violation of norms relating to infrastructure, faculty and willingness to engage a third party for independent assessment of the quality of the training imparted.

The alarming state of teacher education in the country is reflected in the fact that, in recent years, the majority of graduates that have appeared for the central Teacher Eligibility Test have failed to demonstrate even the most basic knowledge base expected from a teacher.

This is not to mention the vision, skills and values necessary for the kind of classroom envisioned by progressive policy documents but which for the most part are not adequately addressed by teacher training programmes. Although a range of committees and policy documents in recent decades have decried the worrying state of teacher education and have made many recommendations for its urgent reform, the majority of these proposals are yet to be implemented.

While demand for more teachers has, in recent years, led to an explosion in the number of teacher education institutions and courses at various levels, this has not been coupled with a push on infrastructure, faculty expertise, learning resources or quality. A greater challenge is that more than 85 per cent of these teacher education institutes are in the private sector where the State has exerted little quality control. No doubt, my

colleagues and seniors in this august House have already shared their erudite views on this issue, and it is for the House to strike a balance between the realities prevailing in the education system today, with particular reference to teacher education, and our capacity to build up teacher training infrastructure as planned under the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017, and go by the wisdom and judgement available in hindsight. I hereby recommend that the Bill be passed by the House. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much, Shrimati Wansuk Syiem. Now, Mr. Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Thank you, Mr. Vice Chairman, Sir. I was not scheduled to speak, but I was provoked to speak by the comments made by a very thoughtful, very sober and a very powerful speaker, Mr. Vinay Sahasrabuddhe.

Sir, he started his otherwise very enlightening speech with an extraordinary attack on all rights-based legislations passed between 2004 and 2014 and described them as *jumlas*. The Right to Information, RTI, Act is a *jumla!*. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is a *jumla!* The Forest Rights Act, 2006 is a *jumla!* The Right to Education Act, 2009 is a *jumla!* The National Food Security Act is a *jumla!* The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 is a *jumla!* The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 is a *jumla!* Sir, this is extraordinary, but it is not surprising, because he belongs to a Party whose President, when he was asked about the Rs. 15,00,000 to be deposited in every bank account said 'वह तो चुनावी जुमला था।' Sir, the Prime Minister is very fond of acronyms and I would like to suggest that the BJP should be rechristened 'Bharatiya Jumla Party', not the Bharatiya Janata Party.

Sir, Mr. Sahasrabuddhe said that the Right to Education Act was prepared in a hurry and passed in a hurry. I would like to remind Mr. Sahasrabuddhe that Article 21A was introduced in the Constitution of India. Article 21A reads, "The State shall provide free and compulsory education to all children between the ages of six and 14 years in such manner as the State may by law provide." This Article 21A was introduced in the Constitution in the year 2002 by the 86th Amendment when Shri Atal Behari Vajpayee was the Prime Minister, and it is in continuation of that Article 21A that the Right to Education Act became a reality in 2010. It took eight years of preparation, eight years of homework.

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: Sir, just a minute.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, let me finish. I heard you patiently; please hear me patiently.

Sir, to say that this Act was prepared in a hurry and passed in a hurry is a complete rewriting of history, and you are not taking credit for your own Prime Minister's achievement which is Article 21A.

Sir, my one and only question for the Education Minister is the following. In the year 2013-14, the budgetary allocation for *Sarva Siksha Abhiyan* was Rs. 24,812 crores. In 2017-18, the budgetary allocation for *Sarva Siksha Abhiyan* is Rs. 23,500 crores. The Central budgetary allocation for *Sarva Siksha Abhiyan* has come down. In the year 2013-14, the budgetary allocation for the Mid-day Meal Scheme was Rs. 10,918 crores. In the year 2017-18, budgetary allocation for the Mid-day Meal Scheme has come down to Rs. 10,000 crores. I would like to ask the hon. Minister how, in the light of the declining budgetary allocation for *Sarva Siksha Abhiyan* and the Mid-day Meal Scheme, the objectives under the Right to Education Bill will be fulfilled.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: Sir, may I clarify, as he has referred to my name?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh, why did you refer to his name? ...*(Interruptions)*...

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: Sir, I would give just a one minute-explanation or rather, just one statement to clarify my point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If he has referred to your name, you can explain; no problem.

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: Sir, I always listen to Mr. Jairam Ramesh with rapt attention and I must say that it enlightens us. Still, let me also clarify here that what I observed was not about the 2002 Constitutional Amendment; it was about the Act which was thereafter enacted by them. The very fact that we have to amend it within such a short span of time makes it abundantly clear that proper application of mind was perhaps missing. ...*(Interruptions)*... Otherwise, why would we have been required to amend it in such a short span of time? ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: The whole thing ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Viplove*ji,* your name was not mentioned. ...*(Interruptions)*...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सवाल केवल होमवर्क का है। **...(व्यवधान)...** सवाल इस चीज़ का है कि जितनी पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी, जितनी प्रामाणिकता से उसके बारे में सारी भूमिका बनानी चाहिए थी, वह नहीं हुआ और आनन-फानन में, एक दृष्टि से लोक-लुभावन वायदे के मोह से यह बनाया गया, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है, You may disagree with this.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I have a serious point. Sir, the Right to Education Act has got a history, and the Constitution Amendment 2002 enactment is a part of that history. To put the political motive in it by *Lok Lubhavan,* etc., etc., is unfair to the entire project. That does not behove us a right culture at the political debate which is meant for this House. ...*(Interruptions)*... So, one thing is very clear. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeev Shukla, do you want to speak? ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, let me complete. ...*(Interruptions)*... Please let me complete. Making teachers trained after the law is passed could not be fulfilled as the whole thing is in the Concurrent List. I have personally taken initiative. His predecessor, Smriti Irani*ji,* is here. ...*(Interruptions)*... Out of that experience, now, it has come in the form of a law. ...*(Interruptions)*... It is welcome; everybody is supporting it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even though all names got exhausted, two requests are before me. One is from Shri Rajeev Shukla and the other is from Shrimati Roopa Ganguly. I can give each of them three minutes.

SHRI BHUBANESWAR KALITAI (Assam) : Sir, Shri K.C. Ramamurthy also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; his name was not in the list. You said, 'in place of Shri Rahman Khan' and रहमान खान साहब बोल चुके हैं।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Please allow him to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different thing. ...*(Interruptions)*... Let me see. Three Members mean nine minutes. But it should be strictly three minutes each. After three minutes, nothing will go on record..

श्री राजीव शुक्ल: उपसभापति जी, यह जो पूरी बहस हुई है, उसमें यह बात समझ में आई है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके लिए पैसे की कमी है। जयराम रमेश जी ने भी प्वाइंट आउट किया है और बाकी सभी के भाषणों से भी पता चलता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा नहीं है, टीचर्स रखने के लिए पैसा नहीं है। इसी तरह से जो हायर एजुकेशन है, उसमें भी वही समस्या है कि रिसर्च और अन्य कामों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। चूँकि मैं योजना मंत्री रहा हूं, इसलिए मंत्री जी को दो सुझाव देना चाहता हूं। इनके यहाँ, भारत सरकार में कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिन स्कीम्स में हजारों करोड़ रुपया जाता है, लेकिन वह पैसा पूरी तरह से बरबाद होता है, उसकी कोई accountability नहीं है। मैं उदाहरण के लिए प्रौढ़ शिक्षा का हाल बताता हूं। हर पंचवर्षीय योजना में 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान होता है, लेकिन हमें आज तक प्रौढ़ शिक्षा से पढ़ा हुआ एक भी आदमी नहीं मिला, आप लोगों को मिला हो तो मिला हो, हमें नहीं मिला। वह सारा पैसा एनजीओ कहाँ लेकर जाता है, इसका कुछ पता नहीं है। यदि वही पैसा प्राइमरी एजुकेशन में डायवर्ट किया जाए, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है, जैसे कि इनका "लिटरेसी मिशन" है। एक स्कीम में पुस्तकें अर्थात् बुक्स सप्लाई की जाती हैं, लेकिन उनकी रसीदें सिर्फ कागजों पर जमा होती हैं और बिल्स दिए जाते हैं, actually किसी को न किताबें मिलती हैं, न कुछ और होता है। आप इन दोनों स्कीम्स को रिव्यू कीजिए और इनका पैसा उसमें डायवर्ट कीजिए। यदि आप इन स्कीम्स को बंद करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। चतुर्वेदी कमेटी ने भी कुछ रिपोर्ट दी थी, इसलिए यदि आप उनको खत्म करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

तीसरा सुझाव, जो विप्लव जी ने भी बताया था, वह यह है कि एक सबसे बड़ी समस्या, जो जिंदगी भर बच्चे का पीछा नहीं छोड़ती, वह यह है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में, खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह राज्यों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती है। उस आदमी में जिंदगी भर यह inferiority complex रहता है। उसको कक्षा 6 से इस भाषा को पढ़ने का मौका मिलता है। वह डी.एम. बन जाए, आई.ए.एस. बन जाए, आई.पी.एस. बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, उसमें यह भाव रहता है। अगर आप साउथ इंडिया की तरह प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश introduce कर देंगे, तो टीचर्स को नौकरी मिलेगी, साउथ इंडियन टीचर्स को भी नौकरी मिलेगी।

6.00 P.M.

और जो उन बच्चों में हीन भावना रहती है, वह निकल जाएगी, क्योंकि जब कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे आगे पहुंच जाते हैं, तो वे हिकारत की नजर से ऐसे देखते हैं। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जो भी ऐसा क्षेत्र हो, उसमें वह बच्चा हमेशा हेंडीकैप्ड रहता है। इसमें हमारे बहुत से साथी पीछे से सिर भी हिला रहे हैं, इसका मतलब है कि यह समस्या है। चाहे वह राष्ट्रपति बन जाए, चाहे प्रधान मंत्री बन जाए, मुख्य मंत्री बन जाए, उसके साथ हमेशा यह समस्या रहती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे इन तीन सुझावों पर जरूर गौर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shrimati Roopa Ganguly; please stick to the three-minute limit.

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम निर्देशित): माननीय उपसभापति जी, जो आपने हमें बोलने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हम मंत्री जी के इस बिल का तहेदिल से सपोर्ट करते हैं। हमें ऐसा

लगता है कि आज की तारीख में यह बिल बहुत जरूरी है। हमारे कुछ छोटे-एकाध सज़ेशंस हैं। इसमें पश्चिमी बंगाल में से कितने टीचर्स एनरोल्ड हो रहे हैं? मुझे इनके कुछ नंबर मिल जाएं कि ये कहां-कहां से हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर्स और कर्मचारी हैं, उन लोगों का परफॉरमेंस और भी अच्छा हो सकता है, अगर कोई ऐसा नियम बन जाए कि primary school teachers and other staff members will not participate in any political rally on a working day. यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा कोई रूल बनाया जा सकता है, तो बनाएं। इसके साथ ही कोई भी चिल्ड्रन, कोई भी स्कूल चिल्ड्रन कभी भी किसी भी पॉलिटिकल रैली में कभी शामिल न हो सके, इसके लिए कोई प्रबन्ध या कुछ पाबंदी लगाई जा सकती है? इसके अतिरिक्त टीचर्स एप्वॉइंटमेंट में और स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में, जैसे हमारे पश्चिमी बंगाल में करोड़ों के झंझट होते हैं, उन पर मॉनिटरिंग की कोई बात हो सके, मैनेजमेंट हो सके, तो वह हमारे बंगाल के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri K.C. Ramamurthy, please take only three minutes.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, school children today learn everything. They will learn politics also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I did not call you. Shri K.C. Ramamurthy, please.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I would not like to go into the merits of the Right to Education Act. All of us know that it is one of the most encouraging Acts and it has been accepted to be a very good Act in the country. But there are a lot of lacunae in its implementation. Our leader, Shri K. Rahman Khan, Mr. Derek O'Brien and others have mentioned about various lacunae of the Act. I would like to draw the attention of the hon. Minister to Section 29 of the RTE Act which very clearly mentions that the curriculum and the evaluation procedure should be in conformity with the values enshrined in the Constitution. It talks about all round development of the child, building up child's knowledge, potentiality and talent, development of physical and mental abilities to the fullest extent, etc. To ensure this, we need teachers – qualified, committed, motivated and trained. Section 23, on which we are having a discussion today, is added, perhaps keeping in mind the requirements mentioned under Section 29 of the Act.

Sir, I would like to mention about the scarcity of good teacher training institutions in the country. Most of the teacher training institutions, as one of my colleagues has mentioned, are under the private sector only. The Government should seriously think about establishing quality and high-standard teacher training institutions, without which I don't think we will be able to achieve any standard or the goal that we are aiming to reach.

[Shri K.C. Ramamurthy]

Sir, I would like to appreciate the hon. Minister that he has taken a number of initiatives in this regard, at least, now. After a lot of time, this Amendment has come before the Parliament. This Amendment should have come into effect, at least, two years ago. But now he has brought this Bill and now this will come into effect.

Sir, again, I would like to bring a very important point to the attention of the hon. Minister that training is a very important component for any sector. Particularly for teaching sector, if training is not made compulsory at the school level, the teachers will not be able to perform. There should be a rotation of teachers. At every level, we have training. Once you become a teacher, particularly in the primary and elementary level, you will not have any training or any re-orientation. It should be made a compulsory activity and it should be rotated. I am not going to make any more points on this. Many hon. Members including Shri Vinay Sahasrabuddhe, Shri Derek O'Brien, Shri Rahman Khan have mentioned a lot of issues about the implementation of the RTE Act. They have highlighted the failures of the implementation of the RTE Act in a number of situations. Sir, I would like to mention about the Government schools. Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister. ...*(Interruptions)*... Derek *ji*, please let him listen to me first. Kindly hear me. Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to what Shri Rahman Khan rightly mentioned about Government schools. In Karnataka, the situation is that there is a lot of rush coming to the private schools; irrespective of the situation, private school seats are filled up and Government school seats remain vacant. Parents want their children to be admitted to the private schools, and, not the Government schools. Even if there is RTE, they do not want to send their children to the Government schools. ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, I will take only one more minute. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, regarding involvement of management, as Mr. Rahman Khan was rightly mentioning. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. It cannot be allowed. ...*(Interruptions)*... Please sit down.

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, I want one minute only. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, one minute please. Sir, it is regarding the relation between the State Education Department and the CBSE and other boards. A large number of CBSE schools. ...*(Time-bell rings)*... Sir, please permit me. ...*(Time-bell rings)*... Sir, a large number of CBSE schools are built as per the specifications of the CBSE and the fee also is charged as per the facilities provided. The State Government's intervention in all these things, in fixing the fee, in changing the syllabus is too much. There should be a restriction. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please sit down. Time is over. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record.

SHRI K.C. RAMAMURTHY: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing more will go on record. ...*(Interruptions)*... This is very unfair. Those Members who wish to speak, they should give their names before the discussion starts. After that, when the discussion is about to be over, pressurizing the Chair is too much. I am sorry. ...*(Interruptions)*... Your Party has taken twenty-five minutes extra. ...*(Interruptions)*... Had you given the names in advance, I would have managed the time. How can you do like this? I am sorry. Yes, Mr. Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, please take the sense of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. ...*(Interruptions)*... Javadekar *ji,* one second. ...*(Interruptions)*... What he said is correct. Let us sit up to the time the reply is over. ...*(Interruptions)*... Please.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सभी 22 माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस बिल को तहे दिल से समर्थन दिया है। इससे यह साबित होता है कि education political agenda नहीं है, बल्कि education national agenda है। हम सबकी concern एक है, हम सबका लक्ष्य एक है, क्योंकि education empowers. जैसा परवीन बहन ने कहा, education empowers, तालीम ही सब कुछ है। अगर एक खेतिहर मजदूर की लड़की उसी जिले की जिलाधिकारी बनने का ख्वाब साकार कर सकती है, तो वह ताकत केवल तालीम में है। जाति, मजहब और सबसे ऊपर उठ कर यह empower करता है और जीवन को संबल देता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण। माननीय सदस्य सिद्धार्थ जी ने महात्मा फुले जी को याद किया। मैं भी पुणे से

*Not recorded.

[श्री प्रकाश जावडेकर]

आता हूँ। उन्होंने वहीं महिलाओं के लिए अपना शिक्षा का आन्दोलन शुरू किया। महात्मा फुले, शाहूजी महाराज, गोखले जी, तिलक जी, मालवीय जी, सर सैय्यद जी, डा. भीमराव अम्बेडकर जी, इन सबने और बहुत सारे लोगों ने, हर राज्य से बहुत सारे नाम हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि आजादी के आन्दोलन के साथ ही एक राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन भी शुरू किया, इसलिए आज हम यहाँ तक आए हैं।

अब सब लोगों का जो मूल मुद्दा था, वह यह था कि सरकारी स्कूलों की क्वालिटी खराब हो रही है। हममें से बहुत लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। मैं भी जिला परिषद् के स्कूल में ही पढ़ा हूं और उसका नाम था, 'जीवन शिक्षण मंदिर'। मैंने इतना सार्थक दूसरा कोई नाम नहीं देखा – 'जीवन का शिक्षण देने वाला मंदिर'। वह जिला परिषद् का स्कूल था। अगर आज स्थिति बिगड़ी है, तो यह सबकी चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर उस खराबी को दूर करना है और उस परिस्थिति को सुधारना है। इसके लिए हमने पांच initiatives की बात सोची है और इसमें हमें सबका साथ मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

पहला initiative है, Right to Education Act में learning outcomes were mentioned but they were not defined at that time. We have now completely codified the learning outcomes. पहली से आठवीं तक, हर वर्ष में छात्र को किस विषय का कितना ज्ञान निश्चित होना चाहिए, ये learning outcomes अब define हो गए हैं। इस साल सभी स्कूलों में शिक्षकों को handbook दे दी गई है और उस handbook के आधार पर उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। अगस्त के एंड में आपको यह देखने को मिलेगा कि सभी स्कूलों में इसके पोस्टर्स लग जाएंगे कि किस स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या-क्या आना चाहिए। इसके साथ-साथ पेरेंट्स को भी एक pamphlet मिलेगा कि आपका छात्र पांचवीं में है, तो उसको यह आना चाहिए। This brings in accountability of every factor, the stakeholder and the 'STEPP' which you mentioned. This will bring in accountability of schools, teachers, parents, students, and everybody. यही होना चाहिए था। आज तक चाहे पहले के सर्वेज़ हुए हों या National Assessment Survey हो, अगर पांचवीं का छात्र तीसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकता था और अगर सातवीं का स्टूडेंट पांचवीं का गणित नहीं कर सकता, तो यह सामूहिक फेल्योर है। इसी फेल्योर को दुरुस्त करने के लिए learning outcomes की शुरुआत की गई है और मुझे विश्वास है कि यह काम अच्छी तरह से होगा। मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप सब सितम्बर में अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विज़िट करिए, उस समय हम National Assessment Survey भी करने वाले हैं। वहां पर आप देखिए कि क्या सचमुच में ग्राउंड पर बदलाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यह देखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

दूसरा, अब तक होता यह था कि पहली से आठवीं तक परीक्षा नहीं रोकनी है। इसका कारण, उस समय जो विचार किया गया था, वह यह था कि स्टूडेंट्स पर परीक्षा का अनावश्यक प्रेशर न बनाया जाए, पहले से उसको मार्क्स की रेस में न डाला जाए। इसके लिए एक सॉल्युशन दिया गया था कि हम इसका continuous evaluation करेंगे। हालांकि यह उद्देश्य अच्छा लगता है, लेकिन हुआ क्या? इसका scientifically continuous evaluation नहीं हुआ, जिसके कारण पहली से आठवीं तक

learning खाली जा रही है। अनेक जगहों पर तो स्कूल्स mid-day school बन गए हैं। बस स्कूल में आना, खाना और जाना, बाकी की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब होगा यह कि learning outcome के साथ-साथ पांचवीं और आठवीं में परीक्षा लेकर, दो चांस दिए जाएंगे। जैसा आपने कहा, पहली परीक्षा मार्च में होगी, मार्च की परीक्षा में जो बच्चे फेल होंगे, उनकी दूसरी परीक्षा मई में होगी। दूसरी परीक्षा में जो फेल होगा, उसको ही हम detain करेंगे और यह अधिकार भी हम राज्यों को दे रहे हैं।

जब सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हमारी बैठक हुई, तो उस बैठक में यह सामने आया कि 25 राज्यों को तो यह बदलाव चाहिए, लेकिन 4 राज्यों को नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, यह निर्णय हम राज्यों पर छोड़ते हैं। आखिर cooperative federalism में 'सबका साथ, सबका विकास' करना है, तो राज्य भी इसके मूल पार्टनर हैं। पहले एजुकेशन केवल राज्य का ही विषय होता था, लेकिन बाद में यह Concurent List में आ गया। इसलिए मुझे लगता है कि यह सुधार भी accountability को बढ़ाएगा। Survey after survey में छात्रों का जिस तरह का चित्र आता है, अब वह नहीं आएगा।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, देश भर में 2.5 करोड़ बच्चे दसवीं का एग्ज़ाम देते हैं और उन 2.5 करोड़ छात्रों में से केवल सात लाख छात्र, यानी CBSE के आधे छात्र बोर्ड की परीक्षा नहीं देते थे। यह सही नहीं था, इसलिए हमने यह निर्णय किया कि इस साल से बोर्ड कंपल्सरी होगा। यह निर्णय पिछले साल घोषित किया गया था, लेकिन तुरंत इसे लागू नहीं किया गया, एक साल के बाद लागू किया गया। इसका parents, teachers and students सब की तरफ से 90% approval हुआ।

महोदय, सबसे मुख्य कड़ी हैं, टीचर्स, जिनके लिए यह बिल है। टीचर कितनी लगन से सिखाता है, उसमें कितनी teachership है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी बार-बार कहा कि हमें integrated B.Ed. course की तरफ जाना चाहिए। महोदय, जैसे अभी 12वीं के बाद, जिसे लॉ करना है, वह पांच साल का कंबाइंड कोर्स करता है, जो डाक्टर बनना चाहता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, वह वहां जाता है, तो वह सिलेक्शन करता है कि मुझे यह बनना है। वह तय करता है कि मुझे यह बनना है और उसी के अनुसार वह सीखता है। वैसे ही, जिसे टीचर बनना है, वह बीए-बीएड, बीएससी-बीएड, बीकॉम-बीएड करेगा, जिसका इंटिग्रेटेड कोर्स चार साल का होगा और चार साल में वह दोनों डिग्रियां हासिल करेगा तथा टीचर बनेगा। इस प्रकार शिक्षा में सबसे ज्यादा काबिल बदलाव होगा। यह बदलाव भी anvil पर है और इसे भी हम आपके सामने लेकर जल्दी आएंगे।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बहुत सारे राज्य बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। हमने 'शिक्षण मंथन" किया और उसमें सभी राज्यों के अधिकारी, वहां के एनजीओज़, वहां के अच्छे शिक्षक जिन्होंने नवाचार किए हैं यानी जिन्होंने अच्छे-अच्छे इन्नोवेशन किए हैं। अच्छे हैड मास्टर्स, जिन्होंने भी नवाचार किया है और अपने स्कूल को बेहतर किया है, उन सभी को इकट्ठा कर के हमने पांच जगह, दो-दो दिन बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम किया, जिसे हमने "शिक्षण मंथन" कहा। हमें इसी प्रकार से आगे जाना है।

महोदय, अब मैं इस बिल पर आता हूं। इस बारे मे यहां यह मुद्दा उठा कि आप दो साल में 11 लाख टीचर्स को कैसे प्रशिक्षित कर पाएंगे? यह करेक्ट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी ने हमें

[श्री प्रकाश जावडेकर]

बहुत ज्यादा empower किया है। वे पाठ तो पढ़ा ही रहे हैं और सिखा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें अलग से प्रेक्टिकल करने का लेसन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें थियोरिटिकल ज्ञान भी होना चाहिए और उसके कारण शिक्षा में समृद्धि आनी चाहिए। इसलिए 'स्वय प्रभा' के माध्यम से यह कोर्स शुरू होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप भी इस बारे में अपने क्षेत्र में जगह-जगह बताइए। हम 15 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच में सभी 11 लाख टीचर्स तक पहुंचेंगे। हमारे पास लगभग सभी के मोबाइल नम्बर्स और ई-मेल एड्रेस हैं। सबके पास हम इंडिविजुअली पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि आपको स्वयं रजिस्टर करना है। यह रजिस्ट्रेशन फ्री है। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि इसके लिए देश के बेहतर टीचर्स कोर्स तैयार कर रहे हैं। एनसीईआरटी और तीन-चार अन्य बहुत अच्छी संस्थाएं ये कोर्स तैयार कर रही हैं – अच्छा कोर्स तैयार हो रहा है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि अच्छा लेक्चर होगा, ट्यूटोरियल होगा, मैटिरियल होगा, यानी सब होगा। इसके अंतर्गत डिसकशन फोरम के द्वारा प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उनके भी जवाब आएंगे और एग्जामिनेशन होगा तथा सर्टिफिकेट मिलेगा। यह ऑनलाइन रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑफलाइन भी रहेगा। 'स्वयं प्रभा' के माध्यम से दूरदर्शन के चैनल्स के माध्यम से होगा। जिन के घर में दूरदर्शन की पहुंच नहीं है, जो फ्री डिश होती है, 1300 रुपए से सेटटॉप बॉक्स और डिश मिलती है, उन्हें वह लगानी है। वह कैसे लेनी है, वह भी हम सभी टीचर्स को बताएंगे। वे घर में भी पढ़ सकते हैं और अपनी सहूलियत से पढ़ सकते हैं। इसमें मैटिरियल की सीडी भी हम टीचर्स को फ्री में देने वाले हैं। यह जो एग्जामिनेशन की फीस होगी, वह भी मॉडरेट होगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का खर्च है, वह तो है। हम जो प्रिंटेड मैटिरियल देंगे, उसमें भी खर्चा होगा और जो सीडी दे रहे हैं, उस पर भी खर्चा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत थोड़ी फीस में यह सिखाया जाएगा।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें 12 दिन का प्रेक्टिकल होगा, जिसमें हर साल फेस टू फेस ट्रेनिंग होगी, यानी दो साल की ट्रेनिंग में 12-12 दिन का ब्लॉक स्तर पर शिविर होगा। वहां सब छात्र आएंगे, वहां के शिक्षक आएंगे और यह छुट्टी के दिनों में होगा। उसमें प्रत्येक अध्यापक और छात्र का आमने-सामने संवाद होगा और सारी डिफिकल्टीज़ सॉल्व होंगी। हमने यह एक फूलप्रूफ सिस्टम बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि सभी राज्य इस बारे में हमारे साथ हैं। इसमें हमने सभी राज्यों का सहयोग लिया है और सभी राज्य इस स्कीम से सहमत हैं, अतः यह काम अवश्य होगा।

महोदय, चार-पांच अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठे। मैं उनका केवल एक-एक वाक्य में जवाब दूंगा। श्री शमशेर सिंह ढुलो जी ने इंग्लिश मीडियम की क्रेज़ के बारे में कहा, वह सही है। अब है, तो है। अभी-कहा कि इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन मैं आज हिन्दी में इसलिए बोला, क्योंकि इंग्लिश बोलें, तो ही स्मार्ट लगें, ऐसा नहीं होता है। अब लोगों के मन में यह बात आ गई है और अब तो गरीब के मन में भी यह बात आ गई है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। अब स्थिति यह है कि इंग्लिश सीखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहां, महाराष्ट्र में 20 साल पहले स्कूल में पहली कक्षा से इंग्लिश एज़ ए सब्जेक्ट शुरू हो जाती थी। लेकिन English medium एक अलग चीज़ है, उसकी पूरी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा में out of school students कम होते जा रहे हैं।

वर्ष 2014 के आंकड़े हैं कि out of school students 60 लाख थे और अभी 50 लाख ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूं। Census के जो फिगर्स आये थे, उसके बाद स्थिति बहुत बदली। उसके बाद, मेरा अंदाजा है कि यह संख्या अभी 50 लाख के आस-पास है। आपको भी देखने में आएगा कि जहाँ हर समय छोटे-छोटे बच्चे मजदूरी में लगते थे, आज नहीं दिखते हैं, वे स्कूल जाते हैं। इसमें वह भी एक बात है। इसे समाप्त करना है, इसलिए "स्कूल चलो, भई स्कूल चलो" यह एक मुहिम हम शुरू करें और हम सब उसके साथी हों, जैसे गुजरात में करते थे, कि केवल अधिकारी, विधायक और सांसद ही नहीं, बल्कि हर कोई एक-एक ऐसे out of school student को ढूँढ़ कर उसे वहाँ स्कूल में दाखिल करेगा। ऐसा भी एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है।

यहाँ शिक्षकों के non-academic काम की बात आई। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमने clear instructions दिये हैं कि उनका काम केवल Census का होगा, जो कि 10 साल के बाद एक बार होता है। केवल इलेक्शन का काम होता है, जो कि पाँच साल के बाद होता है, उसमें roll बनाने का काम उनके पास नहीं है। फिर अचानक जो disaster होता है, तो उसमें काम होता है। इसके सिवाय कोई non-academic काम टीचर्स को नहीं देने चाहिए, यह हमने कहा है।

अभी प्राइवेट स्कूल्स की बात हुई। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा सबका काम है। अभी रहमान खान जी ने, प्रभाकर कोरे जी ने तथा अन्य लोगों ने भी बहुत सी बातें कहीं। आज वास्तविकता यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का enrolment प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत घट रहा है और प्राइवेट स्कूल्स का 8 प्रतिशत बढ़ रहा है। हम इसको चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। हम सरकारी स्कूलों का दर्जा ऐसा ऊँचा करेंगे कि एक healthy competition में सरकारी स्कूल जीत सकता है, यह हम दिखा कर रहेंगे। आप सबकी मदद से हम यह करके रहेंगे। जैसे आज केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के सीबीएसई का जो result का percentage है, वह उससे ऊपर है। ये सरकारी स्कूल्स ही हैं। आप सब लोग मेरे पीछे क्यों लगते हैं कि KV का कोटा थोड़ा बढ़ा दीजिए? ऐसा जो होता है, इसका कारण यह है कि अगर हम एक सिस्टम लाते हैं, तो एक सरकारी स्कूल भी क्वालिटी दे सकता है। यही बात जिला परिषद के स्कूलों में भी हो, कॉरपोरेशन के स्कूलों में भी हो। KVS जैसी संस्थाओं का भी कैसे विस्तार किया जा सकता है, यह करने की जरूरत है।

टीचर्स को contract पर या ad hoc पर रखना ठीक नहीं है। यह हम उच्च शिक्षा में भी कर रहे हैं, जो मुद्दा एक माननीय सदस्य ने उठाया था। Five-day school का जो concept है, उसमें राज्यों को अधिकार है। उसमें learning के कितने hours होने चाहिए, यह तय है। उसका टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करें और छुट्टी कौन से दिन दें, इसमें उनका अधिकार है। इसलिए they can decide their own.

सर, बाकी बहुत सारे विषय सामने आये हैं। रहमान साहब ने EWS का उल्लेख किया। इसमें 25 परसेंट छात्रों की बात आई। मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में जो 25 परसेंट छात्र जाते हैं, तो उसकी भरपाई का, compensation का पैसा भी सरकार देती है।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): टाइम पर नहीं देती।

श्री प्रकाश जावडेकरः एक मिनट। टाइम पर नहीं देती! अब ऐसा है कि हर चीज़ में हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वह काम charity से होता है। उसका पैसा सरकार देती है। कहीं कम देती है, तो कहीं ज्यादा देती है। कहीं 5,000 रुपए प्रति छात्र देती है, तो कहीं 25,000-30,000 रुपए प्रति छात्र भी देती है। ये पैसे दिए जाते हैं। अभी इरफान का एक बड़ा अच्छा सिनेमा आया था – 'हिन्दी मीडियम'। अगर आपने नहीं देखा हो, तो देखिए। EWS में प्रवेश पाने के लिए लोग क्या-क्या करते हैं और कैसे अमीर आदमी भी खुद को गरीब दिखाने की कोशिश करता है, उसकी कहानी बताने वाला वह 'हिन्दी मीडियम' नामक सिनेमा है। जिनको समय मिले, वे उसे जरूर देखें।

जहाँ तक जयराम जी ने बजट की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका बजट कम नहीं हुआ है। जो अनावश्यक खर्च थे, उसमें जो लीकेजेज़ थे, वे कम हुए हैं। इसलिए वह उतना ही कम हुआ है, बाकी कम नहीं हुआ है। "मिड-डे-मील" नामक स्कीम में, केवल दो स्टेट्स में, सिर्फ आधार का लिंकेज़ करने के कारण 6 लाख students, जो कि students नहीं थे, ghost students थे, उनके नाम पर MDM का जो पैसा जाता था, वह जाना खत्म हुआ। हम ऐसा काम तो करेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा कम नहीं करेंगे।

राजीव जी ने जो प्रौढ़ शिक्षा की बात कही, साक्षरता की बात कही, मैं उसके बारे में भी कहूंगा। हम भी एक कल्पना पर विचार कर रहे हैं कि अब चूँकि हर घर का छात्र स्कूल में है, तो किसी को बाहर से आकर पढ़ाने की क्या जरूरत है? जो साक्षर नहीं हैं, उनको उनके ही बच्चे सिखाएंगे। इससे उसको भी कितना अच्छा लगेगा कि मैंने अपने दादा-दादी को सिखाया, मैंने अपने माँ-बाप को सिखाया और उनको भी कितना अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा मेरा गुरु हो गया, उसने मुझे सिखाया। इस पद्धति पर भी हम काम कर रहे हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं।

श्री राजीव शुक्लः क्या आप प्रौढ़ शिक्षा को खत्म करेंगे?

श्री प्रकाश जावडेकरः आज मैं इतना ही कहूंगा कि इस कल्पना पर हम काम कर रहे हैं। मैं रोज़ ऐसे ही थोड़े-थोड़े आश्वासन दे रहा हूँ। आज इस पर बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे लगता है कि शिक्षा की हर चर्चा यही साबित करती है कि शिक्षा नेशनल एजेंडा है। हम सब को मिल कर उसको अच्छा बनाना है और इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, did you mention about children being asked to go to schools on Saturdays? What about that?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I said that it is left to the States because we have decided on schooling hours throughout the year. इतना देना है, लेकिन अब हर शनिवार को छुट्टी देनी है या एक शनिवार के बाद दूसरे शनिवार को छुट्टी देनी है, that is left to the States.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But childhood is the right of the children and robbing that is not good. ...*(Interruptions)*... You should leave Saturday to the children for playing... *(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I agree. But, Sir, there is also another issue involved, जिसका उल्लेख चार सदस्यों ने किया है कि पेरेंट्स को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। पेरेंट्स एक बच्चे के बारे में ऐसा समझते हैं कि सब कुछ होगा, हमारे सारे dreams पूरे होंगे, एक ही बच्चे में सब होगा। Parents education is also needed. But whatever it is, that is left to the States. The States can take the decision. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; all right.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, before you take up the Bill for voting, a special welcome to all the Ministers who were absent yesterday!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is Right of Children to Free and compulsory Education (Amendment) Bill, 2017. You have moved the motion, isn't it?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I have moved the motion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments (Nos.1 and 2) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving the Amendments?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, before my decision, I have a right to say as to what I feel. The RTE Act was enacted in the year 2009 to provide free and compulsory education to children up to 14 years of age and to provide in-service training to the untrained teachers before 2015.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all correct.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Unfortunately, the training could not be provided to all the untrained teachers—everybody said the same thing—to acquire minimum qualifications, and hence the Amendment Bill. In this Bill, the Government has provided that within a period of time, they would complete the task.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving your Amendments. .. *(Interruptions)*...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I appreciate the spirit of the Government, but having seen the trend of training service, I am afraid that all untrained teachers cannot be covered in four years. Therefore, to help the Government, I have brought an Amendment to say that within five years' period, you propose ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is with the Government. ...*(Interruptions)*...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Anyhow, I will not move the Amendment. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving the Amendments? ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: With your cooperation, we will complete the whole training in two years. That will make education more successful.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Wonderful! It is very good. I am giving inspiration. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Hon. Minister, I just want to make a point. The Bill says that from the commencement of this Bill, from 2017, it is four years. So, four years should be counted from 2017 itself, not from 2015. It was written, "commencement of the Bill". See your own Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Shri Derek O'Brien will explain it to you. It is four years from 2015, and, therefore, it is 2019.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So you have not moved the Amendment. Amendments not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even though it is a small Bill, the discussion was very good. I am sorry for the Members whom I could not accommodate because there were a number of requests. Yet there was a good discussion. Thank you very much for your cooperation. Now, we will take up Special Mentions. Dr. V. Maitreyan. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL) *in the Chair*.

THE VICE-CHAIRMAN: Just mention the heading of the Special Mention. ...*(Interruptions)*... Please maintain order in the House. ...*(Interruptions)*...

SPECIAL MENTIONS

Demand to expedite the clearance of two water desalination projects as proposed by the Tamil Nadu Government

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir. I wish to read it. Chennai is a water stressed city with very limited surface and ground water potential. The present demand-supply mismatch of 500 MLD is expected to widen in the future. Tamil Nadu views desalination as the only permanent solution for Chennai's water problems. Chennai already has an installed desalination capacity of 200 MLD. To bridge the deficit, two additional desalination projects have been conceived. The first project of 150 MLD capacity is proposed to be constructed at Nemmeli, south of Chennai, at a cost of Rs.1,259 crores. This project has already received approval from kfW, the German funding agency for 100 million Euro loan assistance. It has also received assistance of Rs. 506 crores under the AMRUT scheme. The procurement process for this project has already commenced. The second project is an ambitious 400 MLD unit, which along with distribution system improvements, is estimated to cost Rs. 5866 crores. It is proposed on a 50-acre site at Perur, barely 600 meters from the Nemmeli plant. Japan International Cooperation Agency has expressed interest to finance this project through a loan assistance of Rs. 4,350 crores. Both the projects are pending for clearance before the Expert Appraisal Committee for Coastal Regulation Zone, under the Ministry of Environment and Forests. Chennai is fast progressing into a sought-after health tourism hub in Asia drawing more people to the city. In view of the growing need for more water, I appeal to the Government to expedite clearance of both these projects to improve water supply situation in Chennai.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the subject mentioned by the hon. Member.

SHRI A.K. SELVARAJ (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue mentioned by the hon. Member.